खण्ड-07 सत्र-03 / अंक-22

शनिवार 26 मार्च, 2022 / 05 चैत्र, 1944 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा

तीसरा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-07 (भाग-01) में अंक 19 से अंक 24 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

राज कुमार

सचिव

RAJ KUMAR

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप-सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-03 शनिवार, 26 मार्च, 2022/5 चैत्र, 1944 (शक) अंक-22

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	वार्षिक बजट (2022-23)	4-77
3.	अनुपूरक अनुदान मांगें (2021-22)	78-82
4.	विनियोजन (संख्या-02) विधेयक, 2022	83-86

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-03 शनिवार, 26 मार्च, 2022/5 चैत्र, 1944 (शक) अंक-22

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1. श्री ए. धनवंती चंदीला ए.
2. श्री अजय दत्त
3. श्रीमती आतिशी
4. श्री अमानतुल्ला खान
5. श्री अब्दुल रहमान
6. श्रीमती बंदना कुमारी
7. सुश्री भावना गौड़
8. श्री भूपेन्द्र सिंह जून
9. श्री धर्मपाल लाकड़ा
10. श्री गिरीश सोनी
11. श्री जरनैल सिंह
12. श्री करतार सिंह तंवर
13. श्री महेंद्र यादव
14. श्री नरेश यादव
15. श्री पवन शर्मा
16. श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर
17. श्री प्रवीण कुमार
18. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस
19. श्री प्रकाश जारवाल
20. श्री रघुविंदर शौकीन

21. श्री राजकुमार आनंद
22. श्रीमती राजकुमारी ढिल्लो
23. श्री रोहित कुमार
24. श्री शरद कमार चौहान
25. श्री संजीव झा
26. श्री सोम दत्त
27. श्री शिव चरण गोयल
28. श्री सौरभ भारद्वाज
29. श्री सही राम
30. श्री अभय वर्मा
31. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
32. श्री अजय कुमार महावर
33. श्री हाजी युनूस
34. श्री मदन लाल
35. श्री मोहन सिंह बिष्ट
36. श्री ओम प्रकाश शर्मा
37. श्री प्रलाद सिंह साहनी
38. श्री शोएब इकबाल
40. श्री सुरेंद्र कुमार
41. श्री विजेंद्र गुप्ता

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-03 शनिवार, 26 मार्च, 2022/5 चैत्र, 1944 (शक) अंक-22

दिल्ली विधान सभा

सदन 11.00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए ।

माननीय अध्यक्ष (श्री रामनिवास गोयल): सभी माननीय सदस्यों का आज के सत्र में हार्दिक स्वागत है। प्रश्न काल।

माननीय अध्यक्ष (श्री रामनिवास गोयल): नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सब का हार्दिक स्वागत है। हमारे लिए बड़े पूरे सदन के लिए, मेरे लिए विशेष रूप से बड़ा हर्ष का विषय है कि कुलतार सिंह जी संधवान जो स्पीकर बने हैं पंजाब विधानसभा के, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बार जीते हैं अपने हल्के तो दूजी वारी जीत के आए ने, पार्टी दा ओथे बहोत काम ऐन्हां ने कीता है। दूजे सरदार हरपाल सिंह चीमा जी। दूजी वारी जीत के आए ने। लीडर आफ अपोजिशन रहे पिछली वारी ते ऐदके पंजाब दे वित्तमंत्री दा दायित्व ऐन्हां दे कंधे आया। ओनां दे बहोत बहोत विधानसभा वल्लो बहोत बहोत स्वागत है। ओनां दे काफी साथी आए ने ओथो,

ओनां दे बहोत बहोत स्वागत है। वार्षिक बजट का प्रस्तुतीकरण, अब मैं माननीय मनीष सिसोदिया जी, उप मुख्यमंत्री वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वार्षिक बजट सदन में प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, मैंने एक notice आपके पास भेजा है।

माननीय अध्यक्षः वो मैंने देख लिया है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः Hon'ble Chief Minister ने हाऊस में गलत बयानी की है उस पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ, आपका।

माननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी, अब आ गया मेरे पास मैं।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः नियमानुसार जो कार्यवाही हो सकती है।

माननीय अध्यक्षः हां वो मैं सुना देता हूँ पढ़ के। पढ़ के सुना देता हूँ। मुझे श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष से नियम 66 के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई है। ये सब मेरे विचाराधीन है और मैं इसकी जांच करने के बाद अपनी व्यवस्था दूँगा। माननीय वित्त मंत्री जी।

श्री मनीष सिसोदिया (माननीय उप मुख्यमंत्री): धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्मानित सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है

और मैं बहुत गर्व के साथ ये सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ कि ये हमारी सरकार का और मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा लगातार 8वां बजट है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में तैयार किए गए और इस सदन द्वारा पास किए गए पिछले 7 budgets की बदौलत आज दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम हुए हैं जिनसे आज देश के कई राज्य सरकारें, देश की कई राज्यों की सरकारें प्रेरणा ले रही हैं। स्कूल बने हैं, नए विश्वविद्यालय बने हैं, अस्पताल बने हैं, मोहल्ला क्लीनिक बने हैं, दिल्ली की जनता को 24 घंटे बिजली मिल रही है और करीब 75 परसेंट घरों में बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। दिल्ली मेट्रो और बसिस का खूब विस्तार हुआ है, सड़कों और मेट्रो लाइन का नेटवर्क बढ़ा है। दिल्ली की गली गली में सीसीटीवी कैमरे लगाकर अपराध रोकने में और महिला सुरक्षा की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। युवाओं के लिए फ्री वाईफाई नेटवर्क उपलब्ध हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाए यहां से पिछले 7 जो बजट पास हुए, उनसे डेवलप हुई हैं। सरकारी सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी जैसी अभूतपूर्व सुविधा की शुरूआत यहां से हुई जिसमें लोग सरकारी दफतर के चक्कर नहीं काटते, सरकारी दफतर के लोग, सरकारी दफतर का कर्मचारी लोगों के चक्कर काटता है, ये अदभुत शुरूआत दिल्ली में हुई। सरकारी दफतर में जिस काम के लिए आम आदमी को धक्के खाने पड़ते थे, कोई दलाल ढूढंना पड़ता था और उसको रिश्वत देकर काम

करवाना पड़ता था आज वो काम सिर्फ एक फोन करने पर घर बैठे हो रहा है ये करिश्मा भी दिल्लीवासियों ने पिछले 7 साल में दिल्ली में देखा है। इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए पिछले 7 बजट के स्फल क्रियान्वयन के चलते पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने विभिन्न विभागों और संस्थानों में ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं सदन के समक्ष रख रहा हूँ कि इस सदन में पिछले 7 बजट के फलस्वरूप, उसके स्फल क्रियान्वयन के फलस्वरूप दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों में 1,78,000 से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी दी गयी है पिछले 7 साल में। इसमें से 51307 नौकरियां तो पक्की सरकारी नौकरियां हैं। और जो पिछले 7 साल में ये 51,307 नौकरियां पिछले 7 साल में DSSSB की परीक्षा ले कर दी गयी हैं और यहां अध्यक्ष महोदय यह भी जानना जरूरी होगा कि हमसे पहले 2015 से पहले की सरकारों में करीब 9 साल तक 2013 से पहले की सरकारों में करीब 9 साल तक न के बराबर नौकरी दी गयी। उन्होंने सरकारी नौकरी देने के लिए जो DSSSB का परीक्षा तंत्रा था उसको पूरी तरह ठप्प करके रखा हुआ था। मुझको याद है कि 2013-14 में 49 दिन के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो उस वक्त DSSSB की जिम्मेदारी मेरे पास में थी। मैंने उस वक्त DSSSB के अधिकारियों को एक ह्त्ते तक 49 दिन में लगभग लगभग मैंने एक हफ्ते तक मीटिंग की कि भई नौकरियां

क्यँ नहीं मिल रही लोगों को, ये सरकारी पद इतने खाली क्यँ पड़े हैं। मैंने उनसे प्लान बनाकर लाने को कहा, अपनी उस वक्त की क्षमता के अनुसार DSSSB के अधिकारी मेरे सामने एक प्लान लेकर आए, मैंने उनसे पूछा कि उस प्लान के हिसाब से जितनी वैकेंसीज़ हैं वो कितने समय में भर जाएंगी? तो उन्होंने खुद बोला कि 38 साल लगेंगे उन नौकरियों को भरने में, ये सारी नौकरियां जो 51,307 नौकरियां भरी गयी हैं उस वक्त मुझे बताया गया 38 साल लगेंगे। लेकिन उस वक्त हमने जो भी क्षमता उनकी बढ़ा सकते थे, बढ़ाई और आज बहुत गर्व हो रहा है मुझे 7 साल बाद कि DSSSB ने अपने काम की जब स्पीड पकड़ी तो 7 साल में दिल्ली में 51,307 युवाओं को नई नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी गयी, पक्की नौकरियां दी गयी, पक्की नौकरियां। इन पक्की सरकारी नौकरियों के साथ साथ दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज़ में करीब ढाई हजार पक्की नौकरी दी गयी, अस्पतालों में करीब 3 हजार पक्की नौकरी दी गयी और 7 साल के दौरान 25 हजार नए युवा टीचर्स को गेस्ट टीचर्स के रूप में रखा गया, इसी तरह करीब 50 हजार नौकरियां सैनिटेशन और सिक्योरिटी के लिए भी रखी गयी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के माध्यम से दी गयी। तो मात्रा 7 साल में दिल्ली में 1,78,000 युवाओं को नई नौकरियों के अवसर सरकार में मिलना कोई छोटी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। और ये तो सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात कही मैंने, उससे जुड़े हुए संस्थानों की बात कही। पिछले 7 साल में दिल्ली में 24 घंटे बिजली

मिलने लगी, infrastructure में डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन और हेल्थ की फेसिलिटीज में डेवलपमेंट हुआ, एक ईमानदार सरकार काम कर रही है। व्यापार के लिए, ट्रेडर्स के लिए जीरो रेड पॉलिसी लागू की गयी, ease of doing business की सुविधा दी गयी। इस सब की वजह से प्राइवेट सेक्टर खासतौर से लघु और मध्यम वर्ग के जो व्यवसायी हैं वो खूब फले-फूले हैं दिल्ली में और उससे प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब में खूब बढ़ोतरी हुई है। इसका एक नतीजा हमें देखने को मिला कि दिल्ली रोजगार पोर्टल जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर शुरू हुआ कोविड के ठीक बाद, उसमें प्राइवेट सेक्टर में 10 लाख नौकरियां तो केवल कोविड के बाद के समय में हमको देखने को मिली। अध्यक्ष महोदय, पिछले 7 साल में इस सदन में प्रस्तुत बजट प्रस्तावों और योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गयी है और यही वजह है कि 7 साल में शिक्षा और स्वास्थ्य में हुए दूरदर्शी निवेश के कारण कोविड महामारी के बीच भी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इसलिए संभल पाई क्योंकि कोविड से पहले के बरसों में यहां पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर काफी निवेश किया गया था। अस्पतालों में डाक्टर्स, नर्सिस, सपोर्ट स्टाफ, नए बेड्स, वेंटिलेटर और बाकी उपकरण की कमी इसलिए नहीं हुई या हुई तो बहुत कम कमी रही क्योंकि कोविड के पहले के 5 साल में इस सदन में जो बजट प्रस्तुत किए गए उन सब में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत समझदारी से और प्राथमिकता के आधार पर निवेश किया गया।

अध्यक्ष महोदय, कोविड की महामारी से तो हम निपट लिए लेकिन हम सब वाकिफ हैं कि पूरे देश में भी और दिल्ली में भी बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार और व्यापार को कोविड में बहुत नुकसान हुआ है। तत्काल राहत के लिए पिछले 2 साल में पीड़ित और जरूरतमंद परिवारों और लोगों को वित्तीय सहायता, अनुदान राशि, राशन, भोजन आदि की व्यवस्था कुछ करके फौरी मदद तो की गयी लेकिन फौरी मदद तो गैरी मदद होती है। इस सदन में अपने 8वें बजट में आज अपने 8वें बजट में मैं दिल्लीवासियों के लिए नए रोजगार सृजित करने और अर्थव्यवस्था को कोविड, जीएसटी, नोटबंदी जैसे तमाम कारणों से पिछले सालों में हुए नुकसान से उबारने का एक एजेंडा लेकर आया हूँ। इससे व्यापार और उद्योग जगत को प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे दिल्ली के नागरिकों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार और व्यापार के नए नए अवसर पैदा होंगे। इस बजट में प्रस्तुत योजनाओं और प्रस्तावों से न केवल दिल्ली के युवाओं को उद्यमशीलता के नए अवसर मिलेंगे बल्कि पहले से स्थापित उद्यम और व्यापार को भी कफी बढ़ावा मिलेगा। उनको भी लाभ मिलेगा, वो भी समृद्ध होंगे। मैंने पिछले 7 साल में इस सदन में सरकार की प्राथमिकता के आधार पर आपके समक्ष जीरो टैक्स बजट प्रस्तुत किया, एजुकेशन बजट प्रस्तुत किया, हेल्थ बजट प्रस्तुत किया, इस सदन में मैंने एक बजट ग्रीन बजट भी प्रस्तुत किया। पिछले साल देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया, आज आपकी अनुमति से मैं इस सदन में अगले वितवर्ष के लिए रोजगार बजट प्रस्तुत कर

रहा हूँ। पिछले साल के देशभक्ति बजट में आजादी की 75वें वर्ष में इस सदन के समक्ष दिल्ली सरकार की ओर से यह संकल्प प्रस्तुत किया गया था कि हमें दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बहुत समझदारी से, बहुत दूरदर्शिता से उस तरफ लेकर जाना है कि भारत जब आजादी की सौंवीं वर्षगांठ मना रहा हो 2047 में तो भारत की राजधानी के लोगों की पर-कैपिटा इनकम 2047 की उस वक्त की सिंगापुर की पर-कैपिटा इनकम के बराबर होनी चाहिए, ये हमने आजादी के 75वें साल में यहां सपना देखा था। इस मुश्किल लेकिन संभव लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ योजनाएं तो मैंने पिछले बजट में लाया था, 2047 तक दिल्ली वालों की आय को सिंगापुर वालों की उस वक्त की आय के बराबर ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे अधिक से अधिक दिल्ली वासियों के पास एक सम्मानजनक रोजगार होना चाहिए, उनके पास एक जॉब होना चाहिए, इसलिए बजट में इस बजट में और 2047 को देखे गये सपने को पूरा करने के पहले कदम के रुप में, मैं इस सदन के समक्ष रोजगार बजट आज प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसका नाम है रोजगार बजट। इसमें प्रस्तुत योजनाओं के माध्यम से हम न सिर्फ दिल्ली के बाजारों की और व्यापार की रौनक और उसकी गरिमा को लौटा लाएंगे। 21वीं सदी के वर्तमान और भावी व्यापार को भी हम दिल्ली में प्रोत्साहन देंगे और इन सब प्रयासों से जो मैं इस बजट में रखने जा रहा हूँ। इन सब प्रयासों से अगले पांच साल में दिल्ली में कम से कम 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगे।

20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगे। रोजगार बजट के माध्यम से हमारा लक्ष्य, इस बजट के माध्यम से हमारा लक्ष्य आर्थिक विकास के इंजन को फिर से स्टार्ट करना है। सुदष्टढ़ बनाना है। ये तो है ही लेकिन अध्यक्ष महोदय, 20 लाख नई नौकरियों वाले इस रोजगार बजट के प्रस्ताव और योजनाओं को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले थोड़ी सी चर्चा मैं दिल्ली की आर्थिक परिदृश्य और इस साल के बजट पर रखना चाहता हूँ।

कोविड की पांच लहरों के बीच आई आर्थिक चुनौतियों से अब दिल्ली की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उभर रही है और इसके चलते दिल्ली का जीएसडीपी प्रचलित बाजार मूल्यों पर वर्ष 2020-21 के 7,85,342 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 9,23,967 करोड़ रुपए रहने की संभावना हैं। ये 17.65 प्रतिशत वृद्धि का संकेत है।

मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 2021-22 में दिल्ली की जीएसडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 10.23 प्रतिशत रहने संभावना है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये वृद्धि 8.9 परसेंट की होने का आकलन है। इसका अर्थ है कि हम महामारी पूर्व की जो हमारी आर्थिक गतिविधयां थी दिल्ली में उस स्तर पर लौट रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी के, राष्ट्रीय स्तर पर जो जीडीपी है, उसमें दिल्ली के जीएसडीपी का योगदान 2011-12 में 3.94 परसेंट था उससे बढ़कर इस साल 21-22 में 4.21 परसेंट हो गया है, जबकि दिल्ली देश की कुल आबादी का केवल 1.52 परसेंट है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में मेन योगदान सेवा क्षेत्र का है और प्रचलित बाजार मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में इसका योगदान 83.94 परसेंट है दिल्ली में सर्विस सेक्टर का, जबकि सेकेंड्री सेक्टर का योगदान 13.78 परसेंट और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2.28 परसेंट है। 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 4,01,982 रुपए होने की संभावना है। 2020-21 में ये 3,44,136 रुपए थी। 2021-22 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में 16.81 परसेंट की बढ़ोत्तरी होने वाली है। वर्ष 21-22 के लिए दिल्ली की पर कैप्टा इन्कम राष्ट्रीय औसत 1,49,848 रुपए से 2.7 टाइम्स ज्यादा है। 2020-21 के दौरान दिल्ली के जीएसडीपी में प्रचलित मूल्यों में 1.09 परसेंट और वास्तविक मूल्यों पर 3.86 परसेंट का संकुचन उसका shrink होना कोविड-19 महामारी और इसके नियंत्राण के लिए किये गये प्रतिबद्ध उपायों का असर दर्शाते हैं। हालांकि अग्रिम अनुमानों का संकेत है कि दिल्ली के अर्थव्यवस्था में 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर 17.65 परसेंट और स्थिर मूल्यों पर 10.23 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी।

अब मैं इस साल के लिए करेंट ईयर के लिए संशोधित अनुमान सदन के समक्ष रख रहा हूँ। 2021-22 के लिए पूरा जो हमने बजट रखा था 69 हजार करोड़ के अनुमोदित बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान में 67 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। 67 हजार करोड़ का प्रस्तावित संशोधित अनुमान

2020-21 में 52,468 करोड़ रुपए के वास्तविक व्यय से 27.70 प्रतिशत अधिक है। संशोधित अनुमान राशि 67 हजार करोड़ रुपए में राजस्व व्यय के लिए 50,862 करोड़ रुपए और पँूजीगत व्यय के लिए 16,138 करोड़ रुपए शामिल हैं। पूंजीगत बजट 2021-22 के लिए अनुमोदित बजट अनुमान के 17,201 करोड़ रुपए से कम होकर संशोधित अनुमान में 16,138 करोड़ रुपए का हो गया है। यह मुख्यतः कोविड महामारी के कारण लागू लॉक डाउन के बाद पँूजीगत कार्यों की धीमी गति के कारण है। स्थापना व्यय और अन्य प्रतिबद्ध देयताओं के लिए 2021-22 की अनुमोदित बजट अनुमान 31,200 करोड़ रुपए से बढ़कर संशोधित अनुमान में 32,400 करोड़ रुपए किये जाने का प्रस्ताव है। ऐसा मुख्य रूप से कोविड नियंत्रण संबंधी व्यय के कारण है। स्कीम प्रोजेक्ट के लिए संशोधित अनुमान 2021-22 में 34,600 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। अनुमोदित बजट अनुमान में ये 37,800 करोड़ रुपए था, इस साल करेंट ईयर का।

सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। महोदय वर्ष 2021-22 के दौरान संशोधित अनुमानों में 468.22 करोड़ रुपए की पूरक अनुमान मांग की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम पूरक अनुदान मांगों के लिए सदन का अनुमोदन चाहता हूँ।

अब मै अगले वित्त वर्ष के लिए कुछ बजट अनुमान इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारी सरकार सत्ता में आने से पहले अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का कुल बजट, कुल

व्यय 2014-15 के दौरान 30,940 करोड़ रुपए था। मैंने जून 2015 में 41,129 करोड़ रुपए के अनुमानितव्यय के साथ अपना पहला बजट पेश किया था और मुझे खुशी हो रही है 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए का बजट मैं यहां पर प्रस्तावित कर रहा हूँ। अगले साल 75,800 करोड़ का बजट है, जो 2014-15 के 30,940 करोड़ रुपए के व्यय की तुलना में ढ़ाई गुना हैं। तो तब से लेकर अब तक ढ़ाई गुना आगे आ चुके हैं। 75,800 करोड़ रुपए के बजट में 32,200 करोड़ रुपए स्थापना और अन्य प्रतिबद्ध व्यय के लिए 43,600 करोड़ रुपए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए है। 75,800 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में 2022-23 में राजस्व के तहत् 53,687 करोड़ रुपए और पँजीगत परिव्यय के तहत् 22,113 करोड़ रुपए शामिल हैं। 2021-22 के बजट अनुमान के खर्च में 17,201 करोड़ रुपए पूंजीगत मद के तहत् और 51,799 करोड़ रुपए राजस्व के अंतर्गत थे। 2021-22 की तुलना में 2022-23 में पँजीगत बजट में 29 परसेंट की वृद्धि हुई है, जबकि राजस्व व्यय में केवल 4 परसेंट की वृद्धि हुई है। इससे समझ में आता है सरकार चलाने का और सरकार के काम के खर्चे में जो हमारी रेसियो है वो बहुत अच्छी चल रही है। इसके अलावा 2022-23 में प्रस्तावित पँजीगत परिव्यय 22,113 करोड़ रुपए है, जो 2014-15 के 7,430 करोड़ रुपए के पँजीगत व्यय से लगभग 3 गुना है। 2022-23 का प्रस्तावित बजट अनुमान 75 हजार 800 करोड़ रुपए 2021-22 के बजट अनुमान 69 हजार करोड़

रुपए से 9.86 प्रतिशत और संशोधित अनुमान से 13.13 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2022-23 के लिए 75 हजार 800 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट का वित्त पोषण 47,700 करोड़ रुपए राजस्व से आएंगे, 1,000 करोड़ रुपए गैर-राजस्व से आएंगे, 325 करोड़ रुपए हमेशा की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट से केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी से, 10 हजार करोड़ रुपए लघु बचत ऋण से, 802 करोड़ रुपए पँजीगत प्राप्तियों से, 10 हजार करोड़ रुपए जीएसटी प्रतिपूर्ति से, 1,621 करोड़ रुपए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से और केवल 643 करोड़ रुपए भारत सरकार की अनुदान सहायता से और बाकी प्रारंभिक शेष ओपनिंग बॉलेंस से आएगी।

स्थानीय निकायों में वित्तीय सहयोग के बारे में। अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार स्थानीय निकायों को 4,374 करोड़ रुपए का वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराएगी। इसमें से 2,305 करोड़ रुपए स्थानीय निकायों द्वारा योजनाओं, कार्यक्रम, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सम्बद्ध राशि के रुप में होंगे और 2,069 करोड़ रुपए बेसिक टैक्स assignment के रुप में होंगे। इसके अलावा 1780 करोड़ रुपए की राशि स्थानीय निकायों को स्टैम्प और पंजीकरण शुल्क में हिस्से और एकमुश्त पार्किंग शुल्क के रुप में उपलब्ध कराई गयी है। इस प्रकार हमारी सरकार बजट अनुमान 2022-23 में स्थानीय निकायों को 6,154 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय सहयोग दे रही है अध्यक्ष महोदय।

रोजगार बजट

अब मैं आपके समक्ष रोजगार बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके समक्ष 20 लाख नई नौकरियों वाले रोजगार बजट के महत्वपूर्ण खंड को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसमें मैं दिल्ली की अर्थव्यवस्था को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की और उससे रोजगार के लाखों अवसर पैदा होने की योजनाओं को रखँगा। अर्थव्यवस्था अध्यक्ष महोदय, चाहे दिल्ली की हो या पूरे देश की, उसकी तरक्की का रास्ता अधिक से अधिक लोगों के हाथ में रोजगार देने से खुलता है। अगर दिल्ली के आंकड़ो को हम देखें तो हम पाते हैं कि दिल्ली की ये महत्वपूर्ण एनालाइसिस एक मैंने किया है बजट में रखने के लिए और अब मैं आपके पासरोजगार बजट लेकर आया हूँ। अगर दिल्ली के डेटा को हम देखें तो हम देखते हैं कि दिल्ली की 1 करोड़ 68 लाख की आबादी में केवल 55 लाख 87 हजार लोगों के पास कोई रोजगार है यानि हमारी दिल्ली में केवल एक तिहाई आबादी के हाथ में कोई रोजगार है। इस तरह हमारी एक तिहाई आबादी के ऊपर बाकी की दो तिहाई आबादी की जिंदगी चलाने का भी उसके कंधे पर जिम्मेदारी है और दिल्ली की आंकड़ों की तुलना अगर हम लंदन, सिंगापुर, न्यूयार्क जैसे शहरों से करें तो हम देखते हैं कि लंदन की आबादी 90 लाख है। इसमें से 51 लाख 60 हजार लोग रोजगार करते हैं यानि लंदन में 58 परसेंट लोगों के पास में रोजगार है। वहां की 58 परसेंट आबादी के पास रोजगार है। न्यूयार्क की

आबादी 88 लाख लोग हैं, उसमें से 46 लाख 25 हजार लोगों के पास में यानि की करीब 52.6 परसेंट आबादी के पास में न्यूयार्क में रोजगार है। सिंगापुर की आबादी आज 55 लाख है और इसमें से 36 लाख 43 हजार लोगों के पास में रोजगार है यानि की 67 परसेंट लोगों के पास रोजगार है। तो हम देखें तो लंदन में 58 परसेंट लोगों के पास रोजगार है, न्यूयार्क में 52 परसेंट से ज्यादा लोगों के पास रोजगार है, सिंगापुर में 67 परसेंट लोगों के पास रोजगार है। दिल्ली में 33 परसेंट लोगों के पास में रोजगार है। इसी से अर्थव्यवस्था को आगे खोलने का इस डेटा को हम समझेंगे और कहां फंसी हुई है पर कैप्टा इन्कम और इकोनोमी, उसको समझेंगे तो इससे आगे बढ़ने का रास्ता हमको यहीं से समझ में आएगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम दिल्ली की वर्किंग पोपुलेशन का, वर्तमान में जो हमारी वर्किंग पोपुलेशन 33 परसेंट है वर्तमान में, इससे बढ़ाकर अगले 5 साल में हमारा टारगेट है कि ये 45 परसेंट तक चली जाए। हम कोई ड्रीम नहीं रख रहे हैं कि अचानक ये 67 परसेंट हो जाएगी, 68 परसेंट हो जाएगी, धीरे-धीरे होगी। तो मैं जो योजना इस बजट में लेकर आया हूँ, वह हमारी पूरी योजना यह है कि अगले पांच साल में ये वर्किंग पोपुलेशन 33 परसेंट से बढ़कर 45 परसेंट हो जाए। यानि दिल्ली के कुल जो 1 करोड़ 68 लाख लोगों की आबादी है और इसमें से अभी 56 लाख लोग करीब अभी रोजगार करते हैं हमारा मकसद है कि ये 56 लाख लोग जो रोजगार करते हैं उनकी संख्या 76 लाख हो

जाए इसलिए हमने 5 साल में 20 लाख नये जॉब क्रिएट करने का लक्ष्य रखा है। हम जानते हैं अध्यक्ष महोदय यह लक्ष्य कठिन है लेकिन केजरीवाल मॉडल आफॅ गवर्नेस में मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमारी सरकार ने जॉब क्रिएट करने के लिए प्रमुखता से निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना है:

a. रिटेल सेक्टर

b. फूड और beverages,

c. लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन,

d. ट्रैवल टूरिज्म,

e. एंटरटेनमेंट,

f. कंस्ट्रक्शन,

g. रीयल इस्टेट और

h. ग्रीन एनर्जी।

इन सारे सेक्टर्स में नौकरियां पैदा करने का एक ही तरीका है कि दिल्ली के लोगों के जीवन स्तर में और बाजार में मांग पैदा करना यानी बाजार में नयी डिमांड पैदा करना और डिमांड बढ़ाने के लिए हमको दिल्ली ही नहीं थोड़ा सा क्योंकि जब डिमांड की बात करेंगे तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के करेक्टर को समझना

पड़ेगा। भारत की हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अंतर्मुखी है यानी कि अपनी खपत पर चलने वाली है। हमारी आबादी जो खपत करने वाली आबादी है वही हमारी ताकत है। भारत की जीडीपी का 60 परसेंट हिस्सा आम लोगों की खपत पर आधारित है और इसे और आम भाषा में समझें तो देश की अर्थव्यवस्था का 60 परसेंट आम लोगों की कमाई से उनके खर्चों से चलता है उनकी खरीददारी यानी खपत से चलता है। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का ऐसे में एक ही तरीका है खपत, खपत, खपत। आप अपने नागरिकों की खपत करने की क्षमता बढ़ाईये, अर्थव्यवस्था अपने आप आगे बढ़ती चली जाएगी। दुनिया में आज मैं खपत, खपत, खपत बोल रहा हूँ तो दुनिया में मंदी के दौर से निकलने के लिए बार-बार ये फार्मूला अपनाया गया है। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद में अमेरिका खुद इस रास्ते पर चला गया और इस रास्ते पर चलकर अमेरिका ने खुद को खड़ा किया। 1945 के बाद अमेरिका में राजनेता, कारोबारी, लेबर और उनके लेबर लीडर्स सब, कोई भी हो, सभी देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, वहां माहौल बनाया गया कि खर्च करो और इसके लिए तेज विकास में जो अमेरिका का तेज विकास दिखा इसी खर्च का असर दिख रहा है। 1945 से 1968 के बीच अमेरिका में वहां की सरकारों ने लोगों की न्यूनतम मजदूरी चार गुणा बढ़ाई ताकि वो खर्च कर सकें, ताकि उनके पास खर्च करने के लिए पैसा हो सके। दूसरे महायुद्ध के बाद अपने पैरों पर खड़ा

होने के लिए अमेरिका ने अपनी आबादी को अपनी ताकत बनाया। आज भारत की यूथ भारत की युवा आबादी हमारी भारत की ताकत है। महामारी और महामंदी के प्रभाव से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हमें अपनी इसी युवा आबादी को रोजगार देना होगा ताकि वह खर्च कर सके, युवाओं के हाथ में पैसा होगा तो वह खर्च करेगा, वो खर्च करेगा तो बाजार में मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और उसके परिणाम स्वरूप रोजगार बढ़ेंगे। हमें केवल और केवल रोजगार बचा सकते हैं और बहुत सारे रोजगार हमें लाने पड़ेंगे, ढ़ेर सारे रोजगार हमको लाने पड़ेंगे तभी हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। रोजगार विकास और समानता की गारंटी है खपत के पहियों को आगे बढ़ाने के लिए केवल रोजगार चाहिए। एक पीयू रिसर्च फाउंडेशन है, पीयू रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है कि भारत में कोविड की लहर में ही साढ़े सात करोड़ लोग न्यू पुअर यानि कि नये निर्धन की केटेगिरी में आ गये हैं, नये गरीबों की केटेगिरी में आ गये हैं। रिसर्च बताती है कि 2030 तक भारत में 9 करोड़ जॉब्स की जरूरत होगी। दिल्ली में आज हम इसकी एक आधारशिला रख रहे हैं। दिल्ली में अगले पांच साल में हम कम से कम 20 लाख नये रोजगार पैदा करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं और मैं इस बजट में कई योजनाएं प्रस्तावित कर रहा हूँ जिनका लक्ष्य मेरे द्वारा अभी तक बयान की गई अपेक्षाओं को पूरा करना है और इसमें से कुछ योजनाएं जिनको मैं पहले संक्षेप में बताउंगा फिर थोड़ा सा डिटेल

में रखूँगा कि दिल्ली के जो ेमस दिल्ली का रिटेल मार्किट्स हैं उनके रिनोवेशन और उसमें इनोवेशन की स्कीम्स लेकर आ रहे हैं हम। देश-विदेश के ग्राहकों को दिल्ली में बुलाकर हम शॉपिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली शॉपिंग फैस्टिवल करेंगे दिल्ली में। दिल्ली का होलसेल मार्किट दिल्ली की बैकबोन रहा है तो दिल्ली के होलसेल व्यापार को अपने पुराने करेक्टर को बरकरार रखने के लिए एक तरु हम रिटेल मार्किट के लिए दिल्ली शॉपिंग फैस्टिवल प्रपोज कर रहे हैं तो दूसरी तरु होलसेल मार्किट के करेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए हम दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल, ये अपनी तरह का एक नया फैस्टिवल होगा, दिल्ली होलसेल फेस्टिवल करेंगे। दिल्ली के छोटे-छोटे स्थानीय बाजारों में जो दुकानदार हैं उनको ग्राहकों से जोड़ने के लिए दिल्ली बाजार पोर्टल शुरु करेंगे ताकि उनको सीधे ग्राहक मिलें। गांधीनगर स्थित एशिया का जो सबसे बड़ा वस्त्र व्यापार केन्द्र है उसको दिल्ली गारमेंट हब के रूप में डेवलप करेंगे। नई स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आ रही है सरकार और नई स्टार्टअप पॉलिसी के तहत नौकरी मांगने के लिए खड़ी युवा आबादी को नौकरी देने वाली युवा आबादी में बदलना है। दिल्ली के non-conforming industrial areas का पुर्ननिर्माण करना है उनका re-development करना है। दिल्ली में खूब सारे लोकप्रिय फूड हब्स हैं उनका पुर्नविकास करना है। दिल्ली में क्लाउड किचन एक नया मार्किट है, क्लाउड किचन को स्थापित करना है, उनको नियमित करना है। दिल्ली में नया एक

electronic city बनाएंगे उसकी स्थापना करनी है। दिल्ली में E-Vehicle, solar energy, urban farming जैसी योजनाओं के प्रमोशन से ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए ग्रीन जॉब्स क्रिएट करेंगे। दिल्ली फिल्म पॉलिसी के जरिए टूरिज्म और आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए रोजगार और व्यवसाय के नये अवसर स्थापित करेंगे और दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव का भी आयोजन करेंगे। दिल्ली में दिल्ली सरकार और इसके different departments और इसके द्वारा जितने भी उपक्रम हैं इनसे कराये जा रहे विभिन्न कार्यों के आउटकम में employment audit की एक परंपरा शुरु करेंगे। दिल्ली में रोजगार ढँढ़ने वाले और रोजगार देने वालों को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए और दिल्ली सरकार द्वारा जो पहले रोजगार पोर्टल शुरु किया गया रोजगार पोर्टल 1.0 उसको प्राफेशनल तरीके से और artificial intelligence से लगाकर रोजगार बाजार 2.0 के रूप में पेश करेंगे और स्कूल लेवल पर एजुकेशन के लेवल पर ही entrepreneurship mind-set develop करके।

अब मैं कुछ समय अध्यक्ष महोदय जो मैंने अभी यह संक्षेप में बताया है इनको डिटेल में आपके समक्ष बताना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि दिल्ली बहुत फेमस मार्किट्स का शहर है, बड़े प्रतिष्ठित बाजार हैं दिल्ली में हमेशा इस शहर का गौरव रहे हैं। प्रत्येक बाजार का हर एक बाजार का अपना महत्व है अपना इतिहास है उसकी अपनी पहचान रही है। हर मार्किट की अपनी कहानी है। वर्तमान में सारी दिल्ली के रिटेल मार्किट्स में साढ़े तीन

लाख से अधिक दुकानें हैं जो करीब साढ़े सात लाख लोगों को रोजगार देती हैं। आधुनिक शॉपिंग मॉल के इस युग में भी दिल्ली के जो प्रतिष्ठित established market हैं conventional market हैं उनके प्रति लोगों का अभी भरोसा कायम है। दिल्ली और उसके आसपास के डेढ़ सौ दो सौ किलोमीटर के दायरे में अध्यक्ष महोदय अभी भी लोग हमारे इन परंपरागत प्रतिष्ठित बाजारों से शॉपिंग करना पसंद करते हैं उनमें विश्वास रखते हैं, उसका श्रेय यहां के व्यापारियों को जाता है। यहां के व्यापारियों ने आज भी लोगों के दिल में दिल्ली का माल मतलब भरोसे का माल। दिल्ली की शॉपिंग मतलब भरोसे की शॉपिंग इसको कायम रखा है। यहां इन प्रतिष्ठित बाजारों में दिल्ली में ग्राहकों के साथ कोई लूट-खसोट नहीं होती, धोखाधड़ी नहीं होती, यहां एक अपनेपन का संबंध होता है। इसमें एक पारंपरिक दिल्ली का लोकाचार है, खरीददारी की एक संस्कृति इसकी धरोहर है इन मार्किट्स की। आज दिल्ली के इन परंपरागत बाजारों को इन्फ्रास्ट्रक्चर और बाकी सुविधाओं से मॉर्डन फेसिलिटीज से रिडेवलपमेंट की जरूरत है। इन बाजारों की क्षमता है कि अगर सरकार के सहयोग से इन बाजारों के व्यापार में थोड़ी भी वृद्धि होती है तो यहां लाखों नई नौकरी पैदा हो सकती हैं। तो दिल्ली सरकार स्थानीय मार्किट एसोसिएशंस और दुकानदारों के साथ मिलकर इन बाजारों को आकर्षक और भरोसे का शॉपिंग एक्सपीरियंस देने वाले बाजार के रूप में डेवलपे करेगी और अगले पांच साल में हमारी योजना दिल्ली के इन प्रतिष्ठित बाजारों का पुनर्विकास और

कायाकल्प करके इनको आकर्षक पर्यटक स्थल जैसा बनाने का है। इस कार्यक्रम के पहले चरण के हिस्से के रूप में इस साल से हम पांच बाजारों से इसकी शुरुआत करेंगे और उन्हें भावी विकास के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए अगले वित्त वर्ष में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मात्रा पांच बाजारों के अंदर अगर इनका रिडेवलपमेंट हो जाए और इनको अच्छे से इनका मार्किट बढ़ जाए तो केवल पांच बाजारों के अंदर से पांच साल के अंदर-अंदर कम से कम डेढ़ लाख नई नौकरियां पैदा होंगी।

अध्यक्ष महोदय दिल्ली में शॉपिंग करना अपने आप में एक सुखद और जीवंत अनुभव है। सरकार की योजना है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश से और पूरे विदेश से भी लोग दिल्ली में शॉपिंग के लिए आएं। जितनी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में शॉपिंग के लिए आएंगे उतनी ही तेजी से दिल्ली की इकोनॉमी बढ़ेगी और नये-नये जॉब्स क्रिएट होंगे। दिल्ली में शॉपिंग के लिए देश और दुनिया के लोगों को आमंत्रित करने और इसको एक उत्सव के रूप में शॉपिंग कराने के लिए हर साल दिल्ली शॉपिंग फैस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मूलतः ऐसे उपभोक्ताओं के लिए होगा जो दिल्ली के चुनिंदा बाजारों में अपने परिवार के साथ में शॉपिंग एक्सपीरियंस का आनंद लेना चाहते हैं। दिल्ली के अलग-अलग प्रतिष्ठित बाजारों के साथ मिलकर ये जो प्लान है दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का चार से छह हफ्ते का शॉपिंग फेस्टिवल होगा और फेस्टिवल के दौरान खरीददारों को

तरह-तरह के आकर्षक डिस्काउंट मार्किट की तरु से दिये जाएंगे। इस फेस्टिवल के तीन मुख्य आकर्षण होंगे शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और खानपान। हमारी सरकार दुकानदारों को जो इस शॉपिंग फेस्टिवल में शामिल मार्किट्स और दुकानदार होंगे, रेस्ट्रां के मालिक होंगे, बिजनेसमैन होंगे उनको SGST refund देकर उनको डिस्काउंट अफ़र देने के लिए लोगों को प्रेरणा देगी क्योंकि हमारा मकसद टैक्स क्लेक्शन नहीं है, हमारा मकसद है जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएट तब होगा जब बिजनेस आगे बढ़ेगा। इससे घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या में करीब चार लाख की वृद्धि होगी जिससे होटल, रेस्टोरेंट्स, पर्यटन और अन्य व्यवसायों को व्यापक लाभ होगा और कुल मिलाकर इन क्षेत्रों में नियोजित 12 लाख लोगों के जीवन पर पॉजीटिव असर पड़ेगा और उम्मीद है कि इससे व्यापार में कम से कम 25 परसेंट का व्यापार बढ़ेगा। दिल्ली शॉपिंग फैस्टिवल की तर्ज पर ही अध्यक्ष महोदय दिल्ली के बाजारों के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक और फैस्टिवल हम इस बजट में लेकर आए हैं दिल्ली होलसेल शॉपिंग फैस्टिवल। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल जहां हम उपभोगताओं के नजरिए से सारी योजनाएं बनाएंगे वहीं दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल में दिल्ली के प्रमुख होलसेल बाजारों के साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर और उसके पूरे देश के लोगों के लिए एक नया होलसेल शॉपिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे और वो लोग पहले से भी दिल्ली में होलसेल के लिए आते हैं। हम जानते हैं कि दिल्ली उत्तर भारत में होलसेल का एक बड़ा ट्रेडिंग सेंटर रहा है। आज भी दिल्ली के

पूरे व्यापार का 60 परसेंट होलसेल से आता है, पूरे बाजार का। यह दिल्ली के होलसेल व्यापारियों का भरोसा है, उनके द्वारा स्थापित भरोसा है जिसे हमारी सरकार आधिकारिक रूप से आगे बढ़ाएगी और दिल्ली की होलसेल मार्किट को एक नई पहचान देगी। दिल्ली सरकार इस फेस्टिवल के लिए दिल्ली के होलसेल व्यापारियों के साथ मिलकर इसका आयोजन तो करेगी साथ में होलसेल के जो कस्टमर्स पूरे देश से आएंगे जो परच्येजर्स आएंगे उनके लिए छूट की आकर्षक योजना तैयार करने में भी मदद करेगी।

अध्यक्ष महोदय आज लोग दुनिया भर में चीन के माल की तरु आकर्षित हो रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि वहां की सरकार होलसेल शोपिंग को खूब प्रमोट करती है। चीन के ज़ेयांगकेयुवू शहर में होने वाला होलसेल शोपिंग फैस्टिवल दुनिया के लोगों को वहां खींचकर ले जाता है। वहां तरह-तरह के लोगों को आफर्स दिये जाते हैं और बड़ा गेम चेन्जर है चीन की इकॉनोमी को आगे बढ़ाने में। इन होल सेल की परचेज करने वालों के सामने बात दिल्ली के सामान की आएगी तो हमको पूरा यकीन है कि चीन के सामान के भरोसे के आगे दिल्ली के सामान की प्रति भरोसा सैंकडों गुणा ज्यादा होगा। जब दिल्ली का सामान देश के होलसेल बाजार में अपनी जगह बनाऐगा तो नौकरियों के कितने अवसर पैदा होगें इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। दिल्ली शोपिंग फैस्टिवल और दिल्ली होलसेल शोपिंग फैस्टिवल के लिए मैं इस बजट में ढाई सौ करोड रूपये का प्रस्ताव रख रहा हूँ। दिल्ली में दुकानदार

के व्यापार को आगे बढ़ाने और रिटेल मार्केट को बूस्ट देने के लिए सरकार एक और योजना लेकर आ रही है दिल्ली बाजार। ये माननीय मुख्यमंत्री की एक बहुत विशेष योजना है। इन्होंने इसको conceptualize किया है। हम सब जानते है कि हमारे रिटले व्यापारियों को ऑनलाईन शॉपिंग में कड़ा कम्पीटिशन है। इसे देखते हुए हमने स्थानीय बाजारों के लिए दिल्ली बाजार नाम से एक पोर्टल मंच तैयार करा रहे हैं जिस पर शापर्स वहां आएगें, सेल्र्स भी वहां आएगें, शापर्स भी वहां आकर देख सकेगें, ऑनलाईन परचेजिंग करेंगे। ये गोलोकल होगा। लोकल लेवल के लोग अपने आसपास की दुकान से ऑनलाइन परचेजिंग कर सकेगें। तो गोलोकल को प्रोत्साहित करते हुए हम ये स्थापित करेंगे। 24 घंटे सातों दिन ये वर्चुअल स्टोर के रूप में काम करेगा। ये व्यवस्था हमारे स्थानीय व्यापारियों के लिए जीरो सैटअप कोस्ट, इसमें व्यापारी को कुछ नहीं देना पड़ेगा, दुकानदार को कुछ नहीं देना पड़ेगा। शून्य खर्च पर की जाएगी। दिल्ली बाजार का एक और आकर्षण ये होगा कि दुनिया के किसी भी कौने में बैठा हुआ ग्राहक दिल्ली के जो प्रसिद्व iconic market जैसे चांदनी चौक है, सरोजिनी नगर है, करोल बाग है, इनका पूरा वर्चुअल tour कर सकेगा और वहां से virtual tour करते-करते किसी दुकान में जाकर वहां से शोपिंग कर सकेगा। ये इसका एक बड़ा आकर्षण रहेगा। इसके जरिए हमारे स्थानीय व्यापारी को अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचने में कफी मदद मिलेगी और मैं इस योजना के लिए 20 करोड़ रूपये का प्रस्ताव करता हूँ

जिसमें दिल्ली के दस लाख रिटेल शॉपकीपर्स को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। अध्यक्ष जी, अपने इस प्रयास से केवल रिटेल सैक्टर में हम अगले पांच साल में रोजगार के तीन लाख नए अवसर देख रहे है और अगले एक साल में केवल अगले ही फाईनांसियल में एक लाख बीस हजार अवसर हम इसमें जॉब्स के देख रहे हैं। दिल्ली के बाजार अध्यक्ष महोदय सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ नहीं है बल्कि हमारे मान-सम्मान की वजह भी बनते हैं। दिल्ली का एक ऐसा मार्केट है गांधी नगर का रेडिमेट गारमेंट और टैक्सटाइल बाजार। इसके बारे में हम भी बचपन से कहते रहे हैं और हरेक दिल्ली का आदमी हमेशा गर्व के साथ कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा रेडिमेट गारमेंट अनिल जी सब कहते रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा रेडिमेट गारमेंट हमारे गांधी नगर में है ये हर दिल्ली वाला गर्व के साथ सबको बताता रहा है। इस बाजार का डेली का जो टर्नओवर है, डेली का टर्नओवर 100 करोड़ रूपये से ज्यादा का है और इसमें रोजगार के प्रत्यक्ष और दो से तीन लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। सरकार की योजना है कि रेडिमेट गारमेंट टैक्सटाईल क्षेत्र में दिल्ली की आन-बान-शान गांधी नगर की इस मार्केट को ग्रेट गारमेंट हब के रूप में विकसित करें और यहां से तैयार गारमेंट्स को लोग इस्तेमाल के लिए जब करें तो बड़ी शान के साथ कह सकें कि this is ready made in Delhi इसके लिए कानूनी मान्यता, infrastructure, re-development नए सर्विस सेंटर्स का निर्माण, गांधी नगर की पूरी

रि-ब्रान्डिंग, marketing, re-positioning इसकी जरूरत पड़ेगी इसके लिए हमने पूरा कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम में अगले पांच साल में रोजगार के 40 हजार नए अवसर पैदा होते हुए हम देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय परिदृश्य के ऊपर एक अभी थोडी देर पहले सदन के समक्ष रखा था कि 2030 तक हमारे देश में नौ करोड़ नई नौकरियों की जरूरत पड़ेगी। इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आने वाले समय में इतनी नौकरी आयेंगी कहां से। ये नौ करोड़ रोजागार देगा कौन, पैदा कौन करेगा? पूरे देश के बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन दिल्ली में हमने इसकी एक अनोखी शुरूआत की है कि हम स्कूल के लेवल से ही अपने बच्चों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी पैदा करने वाला बनाएगें। हमने पिछले साल दिल्ली के स्कूल में बिजनेस ब्लास्टर नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया। जिसका मकसद था ग्यारहवीं और बारहवीं में पढ़ने वाले बच्चे को अपने बिजनेस आईडियाज पर स्फलतापूर्वक काम करके दिखाने की हमने चुनौती दी। तीन लाख से अधिक बच्चों ने 51 हजार बिजनेस आईडियाज पर काम किया और आज उनमें से कई हजार ऐसे बिजनेस आईडियाज हैं जिन पर हमारे ग्यारहवीं, बारहवीं में पढ़ने वाले बच्चे लगातार काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और दूसरे लोगों को भी पैसा कमाने का भी अवसर दे रहे हैं। अगले फाईनांसियल ईयर से बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम को दिल्ली के सरकारी स्कूलों के साथ-साथ दिल्ली के प्राईवेट स्कूलों में भी हम लागू कर रहे हैं।

ताकि सरकारी और प्राईवेट दोनों जगह पढ़ने वाले हमारे बच्चे नौकरी मांगने वाले नहीं नौकरी देने वाले बने। उसकी मानसिकता से साथ अपनी पढ़ाई करें और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वर्षो में दिल्ली के सरकारी और प्राईवेट स्कूलों में पढ़ रहे हमारे ये ही बच्चे जब यूथ बनकर देश में खड़े होंगे तो ये ही नौ करोड़ जॉब्स ये ही लोग क्रिएट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब हम कहते हैं कि हमारे बच्चे नौकरी मांगने वाले नहीं देने वाले बने तो मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम उनको उस तरह का स्वरोजगारीही नहीं बना रहे जिस तरह की स्वरोजगारी हमारे मुल्क में पिछले कुछ दशकों में खड़े किये गए हैं। मशहूर आर्थिक पत्राकार अंशुमल तिवारी और अनिंद्य सेन गुप्ता ने अपनी एक किताब में 'उल्टी गिनती' नाम की एक किताब लिखी है। उन्होंने उसमें लिखा है कि ''स्वरोजगारी भारत का सबसे अंधेरा कौना है।'' दिल्ली सरकार स्वरोजगार की इस हकीकत से वाकिफ है। मैं सदन को भी अवगत कराना चाहता हूँ इस के कुछ फैक्टस कि भारत के कामगारों ने हर दूसरा आदमी self-employed है। इसका मतलब है कि भारत में जितने भी लोग कुछ काम कर रहे हैं उनमें से आधे लोग कोई नौकरी करते हैं, आधे लोग self-employed हैं और ये जो हमारे self-employed है ना अध्यक्ष महोदय, मतलब फिफ्टी परसेंट वर्किंग पापूलेशन हमारी self-employed है और इस फिफ्टी परसेंट का 60 परसेंट खेती में लगा हुआ है। बाकी चालीस परसेंट लोग स्वरोजगारी हैं और ये जो लोग काम कर रहे हैं वो कोई

दुकान चला रहे हैं, वर्कशॉप चला रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, रेहड़ी लगा रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं, दुकानदारी कारपेंटर कर रहे हैं, लौहार हैं, इलैक्ट्रिशियन हैं, पेंटर सैलून जैसा काम कर रहे हैं। एक डेटा ये है कि ये देश के इन तमाम स्वरोजगारियों में केवल चार परसेंट स्वरोजगारी ऐसे है जो दूसरे लोगों को रोजगार देते हैं। बाकी सब बामुश्किल अपनी फैमली चला पा रहे हैं या उनकी फैमली के लोग बिना पेमेंट के उनके साथ काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई गलत बात है। स्वरोजगार करके अपना घर चलाना अच्छी बात है। लेकिन ये पूरा समाधान नहीं है। वो समाधान नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर नए–नए जॉब्स के लिए हमको चाहिए। हमें राष्ट्रीय स्तर पर नौ करोड़ अगर जॉब्स क्रिएट करने हैं तो खाली ऐसे स्वरोजगारी खड़े करने से काम नहीं चलेगा जो अपने महीने में 15–16 हजार रूपये कमाते हो, दस हजार रूपये कमाते हों। हमें ऐसे लोग खड़े करने पड़ेंगे जो दूसरे लोगों को वाइट कॉलर जाब्स भी दे सकें। हमें entrepreneurs खड़े करने पड़ेंगे। इसी जरूरत को समझते हुए दिल्ली सरकार ने entrepreneurship mind-set programme और बिजनेस ब्लास्टर शुरू किये हैं। ये इसका समाधान निकाला है और पाठयक्रम का लक्ष्य ये रखा है कि हमारे बच्चे अब नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि स्कूल कॉलेज से पढकर निकलें तो नौकरी देने वाले बनकर निकलें। इस पाठयक्रम से हम दिल्ली के स्कूलों में भविष्य के बिजनेस लीडर्स दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, entrepreneurship को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार

ने start-up policy बनाई है और मुझे सदन के समक्ष ये जानकारी साझा करते हुए खुशी हो रही है केन्द्र सरकार ने भी इस बात को माना है कि आज हमारी दिल्ली भारत की स्टार्टअप राजधानी है। यहां देश के सबसे ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं। दिल्ली के स्टार्टअप इको सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए हमने दिल्ली की स्टार्टअप पॉलिसी को और प्रोग्रेसिव बनाया है। हमारे देश में आज अगर कोई युवा स्टार्टअप सैटअप करना चाहता है तो उसको अपना मूल काम छोडकर जो उसका मूल आईडिया है उसको छोडकर वो सरकार के साथ उलझता है, टैक्स सिस्टम में उलझता है, इन्फोर्समेंट में उलझता है, जीएसटी में, एमसीडी में उलझता है, पेंटैंट के लिए उलझता है, इस जैसे काम में 90 परसेंट समय देता है स्टार्टअप वाला युवा और दस परसेंट अपने मूल काम में देता है। हमारी जो नई स्टार्टअप पॉलिसी बन रही है ये सुनिश्चित करेगी कि स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं का hundred percent समय अपने आईडिया पर काम करने में जाए और जो 90 परसेंट समय इधर–उधर जाता है, इधर–उधर की फोर्मेलिटीज में जाता है वो उसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार ने नई स्टार्टअप पॉलिसी में ली है। सरकार स्टार्टअप के लिए incubation centre बनाएगी। इनकी मार्केटिंग, इनकी mentoring, इनके इन्वेस्टमेंट के लिए सम्मेलन आयोजित करेगी। इनके फाईनांस के लिए बैंक्स और इन्वेस्टर्स से साथ इनका टाईअप कराएगी। इन स्टार्टअप लागू होने के बाद हर साल बजट में इसके लिए मैने 50 करोड रूपये का प्रावधान रखा है इस साल के

बजट में। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने दिल्ली के लिए एक दिल्ली फिल्म पॉलिसी तैयार की है। ये दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण वातावरण तैयार करेगी। दिल्ली की विविध संस्कृतियां, विविध लोग, विविध परिदृश्य फिल्म निर्माताओं को दिल्ली की ओर आकर्षित करते रहते हैं। दिल्ली एक favourite shooting destination रहा है। दिल्ली सरकार अपनी फिल्म पॉलिसी के माध्यम से इसको और बैटर बनाएगी। दिल्ली को राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर की फिल्मों के लिए shooting destination के रूप में बहुत प्राफेशनल तरीके से खड़ा करेगी, ब्रांडिंग तरीके से। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू पूरी तरह से online single window clearance mechanism, e-film clearance होगा जो 25 से ज्यादा स्टेकहोल्डर एजेन्सी जिसमें भारत सरकार की एजेन्सीज भी है, दिल्ली सरकार की भी है। पच्चीस से ज्यादा स्टेक-होल्डर एजेन्सीज के साथ सभी अप्रूवल प्रक्रियाओं को तेजी से ट्रैक करेगा। इस पॉलिसी की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि दिल्ली में जो स्थानीय प्रतिभाएं हैं, स्किल्ड युवा है उनको नौकरी के लिए क्योंकि जब फिल्म शूटिंग्स दिल्ली में बढेगी, एक टूरिज्म बढेगा तो दिल्ली के लोकल टेंलेंट को जॉब्स के नए-नए अवसर मिलेंगे। ये दिल्ली में highly skilled work force भी हम इस पॉलिसी के तहत तैयार करेंगे जिन्हें प्रोफेशनल के रूप में ट्रेंड करेंगे और इसके लिए हमारी सरकार दिल्ली के प्रतिभागी युवाओं को स्कालरशिप भी देगी और इन्टरंशिप भी देगी। फिल्म पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष जी, हर साल

दिल्ली में इन्टरनेशनल फिल्म फैस्टिवल भी आयोजित होगा। इस फिल्म फैस्टिवल के माध्यम से दिल्ली की समृद्ध संस्कृति और विविधता को फिल्मों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। देश भर की फिल्म बिरादरी को फैस्टिवल में बुलाया जाएगा। ये फैस्टिवल टूरिस्ट को भी एक अलग अनुभव देगा एक अच्छा अनुभव देगा। अब थोडा से फूड सैक्टर पर बात करूंगा। दिल्ली की पहचान हमारे यहां के उपलब्ध व्यंजन और भोजन की विविधता भी है। दिल्ली के आकर्षक व्यंजन परांठे, चाट, छोले भटूरे, पकौड़े, गोलगप्पे, कबाब बहुत सारे खानपान है अध्यक्ष महोदय आप सब भी जानते हैं। ये घरेलू और देसी दोनों पर्यटक जब आते हैं तो दिल्ली में destination चुन कर जाते हैं, destination के बेस पर जाते हैं। तो दिल्ली में भोजन और पेय पदार्थ के क्षेत्र में व्यापारी और कर्मचारियों को बढ़ावा देने के लिए हम चार नीति शुरू कर रहे हैं जिससे अगले पांच साल में रोजगार के साठ हजार नए अवसर पैदा होंगे। हम दिल्ली में प्रमुख फूड हब्स की पहचान करेंगे। उनको रि-डव्लप करेंगे और दिल्ली की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के रूप में उनको प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ दिल्ली सरकार दिल्ली में एक नई ूड ट्रक पॉलिसी लेकर आएगी। फूड ट्रक पॉलिसी में फूड ट्रकों को शहर में अलग-अलग फिक्स लोकेशन्स पर रात को आठ बजे से शाम को आठ बजे से रात के दो बजे तक फूड ट्रक्स सर्विस देंगे अपनी। उनको अनुमति दी जाएगी। इससे दिल्ली की नाईट इकोनॉमी भी आगे बढेगी और रोजगार के नए-नए अवसर पैदा

होंगे। रैस्टोरैंट उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में इसकी बहुत मांग बढ़ती है, क्लाउड किचन की संख्या 20 परसैंट हर साल बढ़ रहीं है, हमने इसकी पूरी स्टडी कराई है। तो हर साल 20 परसैंट किचन क्लाउड किचन नये आ जाते हैं दिल्ली में। वर्तमान में दिल्ली में 20 हजार से ज्यादा क्लाउड किचन है और करीब 2 लाख लोगों को डायरेक्ट और 50 हजार लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार ये दे रहे हैं। क्लाउड किचन उन स्टोर्स में शामिल हैं जो nighttime इकोनोमी को भी स्पोर्ट करते हैं। रिवेन्यू जैनरेशन की एक बहुत बड़ी सम्भावना है इस सैक्टर में, क्योंकि इसमें काफी नौकरियाँ भी निकल सकती हैं साथ-साथ में। तो अध्यक्ष महोदय, वृद्धि की अपार सम्भावनाओं को देखते हुए बजट 2022-23 में इस इंडस्ट्री की क्षमता को अधिकतम करने के लिए प्लग एंड प्ले फैस्लिटिज सरकार सिस्टम देगी, प्लग एंड प्ले की सुविधाओं के साथ, इन क्लाउड किचनस को भूमि प्रदान करने और लाइसेंस और नियमों की संख्या को आसान बनाने की योजना हम लेकर आए हैं। ये इंडस्ट्री अगले 5 साल के अंदर 42 हजार, पूरा कैल्कुलेशन किया है हमने, 42 हजार नये रोजगार क्लाउड किचन इंडस्ट्री से निकलेंगे। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से बढ़ रहे सैक्टर्स में निवेश करना जरूरी है अध्यक्ष महोदय। रिटेल और फूड ब्रिवरेज सैक्टर इसका उदाहरण है और जो 25 परसैंट हर साल बढ़ रहा है। इसमें हाईग्रोथ इनकम भी लोगों को मिलती है लेकिन रिटेल सैक्टर में दिल्ली में एक कमी दिखती है, बड़े मॉल्स की। यहां

केवल 10-12 सफलतापूर्वक चलने वाले मॉल्स हैं और एवरेज देखें तो 20 लाख लोगों पर एक मॉल है। इससे यहां की नौकरी और खरीददार जो है एनसीआर चले जाते हैं, गुडगांव चले जाते हैं, नोएड़ा चले जाते हैं। दिल्ली में प्रति एक हजार की आबादी पर मॉल स्पेश की उपलब्धता सबसे कम है। दिल्ली की तुलना में एनसीआर में ये 6 गुणा ज्यादा है। हमारा प्रस्ताव दिल्ली में ग्रेड-ए रिटेल और फूड हब विकसित करना है, ताकि आज लोग खरीददारी के लिए जिस प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए एनसीआर जाते हैं उनको दिल्ली में वर्ल्ड क्लास ब्रांड और रिटेल की सुविधाएं मिल सके। इसके तहत बस डिपो और टर्मिनलस में जो सरकार के पास जमीन उपलब्ध है उसका उपयोग करके वहां पर ये हब विकसित किये जाएंगे, क्योंकि ये दिल्ली के प्रमुख स्थानों तक लोग आसानी से पहुंच सकें और उपभोगताओं के बड़ी संख्या वाले क्षेत्र हैं। ये ग्रेड स्पेस सभी आधुनिक तकनीकों के साथ तैयार किए जाएंगे जो दिल्ली को भारत में एक शानदार शॉपिंग और ़ूड हब के रूप में विकसित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक और नया प्रस्ताव इलैक्ट्रोनिक्स मैन्फुैक्चरिंग से संबंधित है। इलैक्ट्रोनिक्स मैन्फूैक्चरिंग आज दुनिया में सबसे ज्यादा जोब्स देने वाला उद्योग है। इसकी खात बात ये है कि नॉन-पोल्यूटिंग सैक्टर है, परम्परागत रूप से अगर पुरानी चीज देखें तो दिल्ली 70-80 के दशक में भारत में इलैक्ट्रोनिक ट्रेड का सैंटर था। आज भी दिल्ली के इलैक्ट्रोनिक्स और इलैक्ट्रीक्ल मार्केट देश में पूछे जाते

हैं। दिल्ली की खुद की मांग और देश की मांग को पूरी करने के उद्देश्य से हम दिल्ली में एक इलैक्ट्रोनिक सिटी का निर्माण करेंगे, इससे स्थापित हो जाने के बाद 80 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा इसमें। इस प्रयोजन के लिए सरकार बापरोला में 90 एकड़ में प्लग एंड प्ले मैन्यूफैक्चरिंग केंद्र की स्थापना करेगी ताकि इलैक्ट्रोनिक कंपनियों को दिल्ली में अपना बेस स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। हम इस कार्यक्रम को भारत सरकार के इलैक्ट्रोनिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर ई.एम.सी. कार्यक्रम के सहयोग से करने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में दिल्ली में 25 नोटिफाईड नॉन कनफर्मिंग इंडस्ट्रीयल एरिया हैं, जिसमें करीब 16 लाख लोग काम करते हैं। इन क्षेत्रों के रि-डेवलपमेंट की और up-gradation की जरूरत है। अगले 5 साल में दिल्ली सरकार नॉन कनफर्निंग इंडस्ट्रीयल एरिया के रिडवलमैंट पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसके अंतर्गत यहां के एरियाज को ग्रीन बनाएंगे, साफ-सुथरा करेंगे, टिकाऊ बनाएंगे, व्यापार को विकसित करने में यहां की इंडस्ट्री को मदद करेंगे। यहां के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे और इसमें हम डवलपर्स की मदद भी लेंगे ताकि ले-आउट की तैयारी, अप्रूवलस सीवरेज सिस्टमस, सीटीपी वाटर सप्लाई, इंडस्ट्रीयल वेस्ट मेनेजमेंट, रोड डेवलपमेंट ये सारी सुविधाएं वहां पर जुटाई जा सके। सरकार वहां पर कॉमन फैस्लिटी सैंटर्स सीएफसी भी बनाएंगी जिससे इन औद्योगिक क्षेत्रों की जरूरत के अनुसार आरएंडडी एक्सपीरियंस सैंटर, वहां टूल रूम, प्रोसैसिंग सैंटर, मान्यता प्राप्त लैब्स वहां पर हों, बिजनस कन्वैंसन

सैंटर, रो-मैटिरियल बैंक हो, लॉजैस्टिक सैंटर। इसके अलग-अलग सैंक्टर इसमें शामिल होंगे। इन नान-कन्फर्मिंग इंडस्ट्रीयल एरिया के पुनर्विकास के बाद दिल्ली के लोगों के लिए 6 लाख से अधिक जोब के नये अवसर पैदा होंगे, इसका भी हमने पूरी स्टडी कराई है।

अध्यक्ष महोदय, आने वाले पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा और पानी उपलब्ध कराना दिल्ली सरकार के 2047 के विजन का एक हिस्सा है। इसे ध्यान में रखते हुए अगले 5 साल में दिल्ली सरकार ने कई पहल शुरू की है, शुरू कर चुकी है और इससे एक लाख ग्रीन जोब्स दिल्ली में नये बनने वाले हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली की जो ईवी पोलिसी हमने launch की। 18 महीने के अंदर भारत की ईवी कैपिटल हमारी पोलिसी की वजह से दिल्ली में बन गई है। 2019-20 में दिल्ली में नये वाहनों की बिक्री में इलैक्ट्रीक वाहनों की हिस्सेदारी 1.2 परसैंट थी 2 साल पहले, आज ईवी की बिक्री ने 10 परसैंट का आंकड़ा पार कर लिया है दिल्ली में और ये भारत का सबसे नंबर वन स्टेट बन गया है ईवी के सेल में। 10 परसैंटसेल ईवी व्हिकलस की हो रही है, जो यू.के, त्रांस, सिंगापुर इन जैसे देशों से भी ईवी परसैंटेज में हम आगे पहुंच गए है। अब जब ईवी की सेल बढ़ रही है, ईवी की हिस्सेदारी बढ़ रही है रैगुलर ट्रैफिक में तो उसके चलते अगले 5 साल में उसकी मरम्मत के लिए, उसकी मैंटेनेंस के लिए, उसके चार्जिंग स्टेशन के संचालन करने के लिए, उसके रख-रखाव

के लिए 20 हजार नये रोजगार पैदा होंगे केवल ईवी केसैक्टर में। इसके अलावा दिल्ली सरकार अगले वर्ष से 30 परसैंटरिजर्वेशन के साथ महिला ड्राईवरों के लिए 4200 से अधिक ई-ऑटो लेकर आ रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सहमति से अगले 5 साल में हम हर साल 5 हजार ई-ऑटो परमिट जारी करेंगे और इससे 25 हजार नई नौकरी पैदा होंगी।

दिल्ली रूफटॉप सोलर यूंनिटस को अपनाने की दिशा में भी लगातार प्रगति कर रही है। रूफटॉप के 16 प्लांटों की स्थापित क्षमता पहले ही 900 मेगावाट पहुंच गई है। दिल्ली सरकार अगले 5 साल में रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने की क्षमता को 2500 मेगावाट, इसकी पीक तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर नई सोलर पोलिसी लेकर आ रही है, जो दिल्ली की वार्षिक ऊर्जा की डिमांड में 10 परसैंटहम सोलर एनर्जी से बनाएंगे। इससे क्षेत्र में नये जॉब्स पैदा होंगे, सेल्स में, कंस्ट्रक्शन में, निर्माण श्रमिकों के, इलैक्ट्रीशियन के, टैक्नीशियन, इंजिनियर ये सोलर एनर्जी के सैक्टर में भी नये-नये जोबस पैदा होंगे और हमने 40 हजार नौकरियों की स्टडी की है, जो इस सैक्टर में नई बनने वाली है।

दिल्ली के ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए पौष्टिक जैविक भोजन की आपूर्ति के लिए और महिलाओं को घर-घर पर रोजगार देने के लिए एक नई स्कीम सरकार पूसा इंस्टीट्यूट के सहयोग से लेकर आ रही है, 'स्मार्ट अर्बन फार्मिंग'। भारत में किसी भी राज्य के लिए अपनी तरह की ये पहल है जहां दिल्ली सरकार पूरी

दिल्ली के मोहल्लों में वर्कशॉप आयोजित करेगी और 'स्मार्ट अर्बन फार्मिंग' को प्रमोट करेगी, उसको जन आंदोलन बनाने के लिए सब्सिड़ी युक्त सामग्री देगी, प्रशिक्षित माली देगी और दिल्ली की महिलाओं को विशेषतौर पर, लोग अपनी छत पर, अपनी बालकनी में जहां भी उनके पास छोटा सा भी स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस नहीं चाहिए, जितने में हमारे सेक्रेटरी साहब बैठें हैं इससे भी आधे स्पेश में काम हो जाता है। सही में जितने में एक एमएलए हमारे बैठे हैं आलमोस्ट उतने में, एक छोटे घर के लिए अर्बन फार्मिंग का वो लग जाता है और उसको महिलाएं चलाती हैं। दिल्ली में काम होना शुरू हो गया है, सरकार इसको बहुत ओर्गनाइज तरीके से आगे बढ़ाएगी और अर्बन फार्मिंग में महिलाओं की आजीविका भी बढ़ेगी, उनको अच्छा फूड भी, जैविक फूड घर पर मिलेगा और 25 हजार नई नौकरियाँ अर्बन फार्मिंग में क्रीएट होंगी।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार ने 750 करोड़ रुपये की अनुमानित परिव्यय के साथ दिल्ली की 600 से अधिक झीलों और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है जो दशकों से उपेक्षित दिल्ली के जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त करेगी और इन्हें डंप यार्ड में बदल दिया गया था उनको रिजनरेट करेगी। ये इस पैमाने पर इन जलाशयों के चल रहे मरम्मत कार्य, रख-रखाव के लिए 6 हजार से ज्यादा ग्रीन जोब्स पैदा करेंगे ताकि एक बार पुनर्जीवित होने के बाद ये जलाशय खराब भी ना हों, उसकी भी स्कीम हम लेकर आ रहे है।

कोरोना की पहली लहर के बाद जब पूरे देश में अध्यक्ष महोदय करोड़ों लोग बेरोजगार हुए तो दिल्ली सरकार ने नौकरी देने में, नौकरी चाहने वालों को जोड़ने के लिए एक रोजगार बाजार पोर्टल शुरू किया। रोजगार बाजार 1.0 की स्फलता बताती है कि इसमें 15 लाख से अधिक नौकरी चाहने वालों ने रजिस्ट्रेशन किया और 10 लाख नौकरी देने वालों ने रजिस्ट्रेशन किया। इसलिए 10 इसमें नौकरी मिली। इतने कम समय में इतनी ज्यादा नौकरी दिलाने वाला ये शायद किसी भी राज्य का ये सबसे स्फल प्रयोग होगा। इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सरकार अगले साल रोजगार बाजार 2.0 लॉच कर रही है। इसमें आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस और मोबाइल एप्लीकेशन को हम जोड़ रहे हैं। रोजगार बाजार 2.0 में हम जोब्स की स्मार्ट मैचिंग, प्लेसमैंट की ट्रैकिंग, employers के वैरिफिकेशन और एक बहुत मजबूत एनालिटिक्स platform ये इससे लैस करेंगे इसको। इस पोर्टल के माध्यम से हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली के युवाओं को और खासकर महिलाओं को, हर साल कम से कम एक लाख नई नौकरियाँ मिलती रहें। इसके साथ-साथ इस प्लेटफार्म के माध्यम से जो लोग नौकरी चाह रहे हैं उनको टैक्नीकल और उनके सॉफ्ट स्किल को अपग्रेड करने के लिए अलग-अलग ऑनलाइन-आर्फलाइन कोर्सिसज भी हम explore करने में हम मदद करेंगे। carrier counseling उनकी कराएंगे, वन टू वन उनके सैशन कराएंगे ताकि जब employer उनको हायर करे तो उसकी थोड़ी-सी अपग्रेडेशन हो जाए। सरकारी नौकरी और सरकार द्वारा रोजगार संबधी

जो सोशल बैनिफिटस दिए जाते हैं, उनकी भी सारी वैल्यू एडिड सूचनाएं उसपर उपलब्ध होंगी। अध्यक्ष महोदय इस रोजगार बजट का एक अहम उद्देश्य महिलाओं को रोजगार और उनका आर्थिक विकास है। वर्किंग फोर्स में महिलाओं की आबादी की भारत में भागीदारी एशिया में सबसे पिछड़े देशों में से आती है, पूरे इंडिया में। जबकि भारत में पिछले तीन दशक में हमने देखा है कि economic इकोमिक ग्रोथ ठीक-ठाक हुई। लेकिन ये हैरानी करने की बात है कि इस दौरान महिलाओं की वर्किंग फोर्सिसज में नीचे गया। 1999 में 34 परसैंटसे घटकर, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया की वर्किंग ोर्स में वीमेन फोर्स जो है 1999 में 34 परसैंटथी जो 2019 में 20 प्रसैंट रह गई और जो दुनिया भर में देखे जा रहे ट्रेंड के अपोजिट चल रही है। उदाहरण के लिए बंगलादेश में वर्किंग फोर्स में महिलाओं की भागीदारी 30 परसैंट और चीन में 60 परसैंट है। हमारे यहां इंडिया में 20 परसैंट है। इसके अलावा महामारी के दौरान जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई उसमें सबसे ज्यादा जोब्स महिलाओं के गए है। सारे अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि जब तक भारत की महिलाएं देश की वर्किंग फोर्स से बाहर रहेंगी तब तक भारत एक विकासशील से विकसित देश बनने का सपना, सपना रह जाएगा। इसके मद्देनजर इस साल के बजट में जो मैंने अभी कुछ योजनाएं पेश की और आगे जो करूंगा इसमें महिलाओं के लिए अधिक से अधिक स्वरोजगार, अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने पर हम फोकस कर रहे हैं। गांधी

नगर में जो हम रिटेल सेल की बात कर रहे है, डिजाइन रेडीमेड कपड़ों का काम महिलाओं द्वारा किया जाता है, ज्यादातर। गांधीनगर को जैसे ही गारमेंटस डिजाइन और असेंबली के हब के रूप में विकसित करेंगे, महिलाओं के लिए उसमें अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इलैक्ट्रोनिक्स असेंबली इकाईयाँ ज्यादातर महिलाओं को रोजगार देती हैं। दिल्ली के इलैक्ट्रोनिक शहर स्थापना से फिर से महिलाओं के लिए रोजगार के और अवसर पैदा होंगे। दिल्ली में अर्बन फार्मिंग, इलैक्ट्रीक ऑटो, इलैक्ट्रीक बस के चलन में महिलाओं को रोजगार देने के लिए नये अवसर मिल रहे है। रोजगार बाजार 2.0 में भी हम महिलाओं को ज्यादा रोजगार कैसे मिले, उसपर हम खास ध्यान देंगे। इस तरह विभिन्न क्षेत्रों में अगले 5 साल में कम से कम 20 लाख रोजगार पैदा होंगे।

इसके साथ ही सरकार एक और महत्वपूर्ण योजना लेकर आ रही है जो मैंने बीस लाख रोजगार के अलावा बताया कि सरकार अपने हरेक विभाग में दिल्ली सरकार के किसी भी संस्थान में इस सदन द्वारा पास किये जा रहे बजट का एक-एक रूपया जहाँ भी खर्च हो रहा है वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा हो, सड़क बनायी जा रही हो, बिल्डिंग बनायी जा रही हो, पुल बनाये जा रहे हो, स्कूल, अस्पताल, कालेज चलाये जा रहे हो या बनाये जा रहे हो, बिजली-पानी की व्यवस्था में पैसा खर्च हो रहा हो, कॉल सेन्टर, कला संस्कृति की कहीं सेवायें ली जा रही हो। जहाँ भी यहाँ विधान सभा से पास बजट का एक भी

रूपया खर्च हो रहा है उस काम का हम इम्प्लायमेन्ट ऑडिट करवायेंगे। वहाँ से उससे कितने जॉब मिले इसका पूरा इम्प्लायमेन्ट ऑडिट का पूरा प्लान लेकरके आ रही है सरकार और ये पूरे देश में पहली बार होगा कि जनता के टैक्स के पैसे से हो रहे काम से कितने जॉब क्रियेट हुए, उसका भी लेखा-जोखा योजना में भी शामिल होगा और उसका ऑडिट भी करेंगे और जैसा मैंने कहा कि ये सब कार्यक्रम जो मैंने अभी रोजगार बजट के तहत आपके समक्ष रखे। अगले पाँच वर्ष के लिए योजना है हमारी और इनके स्फल क्रियान्वयन से जो नयी नौकरियाँ निकलेंगी, उनमें अगले पाँच साल में कम-से-कम बीस लाख कम-से-कम नौकरियाँ नई निकलेंगी। इन कार्यक्रमों के लिए अगले पाँच साल के दौरान साढ़े चार हजार करोड़ रूपये की जरूरत पड़ेगी। पहले वर्ष के लिए अगले वित्त वर्ष के लिए मैं इसमें 800 करोड़ रूपये का बजट प्रस्ताव रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ी सी बात स्वास्थ्य सेवाओं पर करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सदन में प्रस्तुत पिछले सात बजट में हर बार शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता रहे हैं। दिल्ली में रह रहे हर नागरिक के लिए चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरूष हो, हर व्यक्ति के लिए बेस्ट आफॅ दि बेस्ट हेल्थ फैसिल्टीज उपलब्ध कराना माननीय मुख्यमंत्री जी के गवर्नेंस मॉडल का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। नये अस्पताल बनाने से लेकरके मोहल्ला

क्लीनिक जैसी अवधारणा पर स्फलतापूर्वक काम करके केजरीवाल सरकार की पिछले सात साल की बड़ी उपलब्धियों में से हेल्थ सेक्टर रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार दिल्ली के नागरिकों को 520 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक दे चुकी है। 29 पॉली कलीनिक, 38 मल्टी स्पेशियल्टी/सुपर स्पेशियल्टी हॉस्पिटल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवायें दे रही है। 94 पॉली क्लीनिक मौजूदा औषधालयों का उन्नयन का स्थापित किये जा रहे है। मोहल्ला क्लीनिकों की संख्या भी बढ़करके 1000 होगी। 2022-23 के बजट में आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक और पॉली क्लीनिक के लिए मैं 475 करोड़ रूपये का बजट रख रहा हूँ। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा स्थापित मोहल्ला क्लीनिक के मॉडल की सफलता को देखते हुए बुराई कोई भी करता रहे लेकिन देश के लगभग-लगभग सारे राज्यों के छोटे-बड़े कस्बों में मोहल्ला क्लीनिक बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं सारे राज्यों में। किसी और नाम से कर रहे हैं। कहीं मोहल्ला क्लीनिक कह रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। 2015 में मोहल्ला क्लीनिक सत्येन्द्र जैन जी ने और माननीय केजरीवाल जी क्यों conceptualize किये, क्यों बनाये और मोहल्ला क्लीनिक में कौन सी समस्या का समाधान किया है, इस पर मैं दो मिनट लूँगा। आज रोजगार बजट मैं रख रहा हूँ तो मोहल्ला क्लीनिक भी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एलीमेन्ट है और उसकी आधारशिला पिछले पाँच-सात साल में रखी गयी और उस पर मैं बात रख रहा हूँ। हमें समझना होगा अध्यक्ष महोदय कि भारत की नई गरीबी बीमारी

से निकल रही है। भारत में जो नया गरीब पैदा हो रहा है वो बीमारी से पैदा हो रहा है। भारत में हर साल साढ़े 5 करोड़ लोग यानी की पूरी आबादी का 4.6 परसेन्ट बीमारी की वजह से गरीबी में जा रहे हैं। इनमें से 72, जो ये साढ़े 5 करोड़ लोग मैंने बताया पूरे इण्डिया में, इनमें से 72 परसेन्ट केवल प्राइमरी हेल्थ पर उनका जो खर्च हो रहा है उसके कारण गरीब हो जाते हैं। इसलिए मोहल्ला क्लीनिक यही पर आवश्यकता बनती है। ये प्रयोग दिल्ली में स्फल हुआ और आज अगर दिल्ली की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, दिल्ली की इकोनॉमी बढ़ रही है और महामारी और महा मंदी के दौर में अगर दिल्ली की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती रही तो इसमें मोहल्ला क्लीनिक ने एक अहम भूमिका निभायी है। मुझे सदन को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक 5 करोड़ 49 लाख मरीज इन मोहल्ला क्लीनिक में उपचार लेकरके जा चुके हैं। यही वो लोग हैं अध्यक्ष महोदय, यही वो लोग हैं अगर इनको समय पर सही से प्राथमिक उपचार नहीं मिलता, मोहल्ला क्लीनिक में अच्छा डॉक्टर इनको निःशुल्क सुविधा नहीं देता, एक एमबीबीएस डॉक्टर इनका इलाज नहीं करता तो सम्भवतः इनमें से भी बहुत सारे लोग बीमारी के कारण देश के नये गरीबों में शामिल हो जाते। दिल्ली सरकार ने आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक को विस्तार देते हुए दिल्ली के स्कूलों में भी अब आम आदमी स्कूल क्लीनिक शुरू किये हैं। फिलहाल 20 स्कूल से ये क्लीनिक शुरू किये गये है और इसमें हर बच्चे का हर 6 महीने में चेक अप किया

जायेगा एक योग्य डॉक्टर और नर्स के द्वारा। साथ ही हर आम आदमी स्कूल क्लनिक में एक मनोचिकित्सक भी लगाया जा रहा है ताकी बच्चों के मानसिक विकास की, उनकी मानसिक उलझन की, उनकी अगर वो किसी मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं तो उसकी भी जॉच हर 6 महीने में हरेक स्कूल में बच्चे की होती रहे। ये स्कूल क्लीनिक का काम है। हमारी सरकार ने मौजूदा अस्पतालों के विस्तार, अपग्रेडेशन और नये अस्पतालों का निर्माण कार्य शुरू किया है। इसके तहत बुराड़ी में 768 बिस्तरों का अस्पताल पूरा हो चुका है और कोविड रोगियों के लिए साढ़े चार सौ बिस्तरों के साथ वहाँ काम कर रहा है। इसी प्रकार अम्बेडकर नगर अस्पताल भी कोविड रोगियों के लिए 200 बिस्तर की क्षमता के साथ काम शुरू कर चुका है। इन्दिरा गाँधी हास्पिटल, द्वारका में भी कोविड रोगियों के उपचार की व्यवस्था हो गयी है। अगले साल से ये अस्पताल 1241 बिस्तरों की अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देगा। 15 मौजूदा अस्पताल की भी रि-मॉडलिंग का काम शुरू हो गया है और इसके अलावा 4 नये अस्पताल के लिए प्रपोजल बनाये जा रहे हैं। नये अस्पतालों के बन जाने और मौजूदा की रि-मॉडलिंग होने से इसके बाद 16000 बिस्तर दिल्ली में नये उपलब्ध हो जायेंगे। मैं नये अस्पतालों के निर्माण और मौजूदा सरकारी अस्पतालों की रि-मॉडलिंग के लिए 1900 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय दिल्ली आरोग्य कोष के तहत ये भी एक माननीय मुख्यमंत्री जी के विजुलाइज की गयी एक बहुत इम्पार्टेन्ट

और बहुत जनोपयोगी सेवा है। दिल्ली आरोग्य कोष के तहत नि:शुल्क उपचार, सर्जरी, रेडियोलॉजी, क्लीनिकल सेवायें उन रोगियों को निजी अस्पतालों के जरिये उपलब्ध करायी जा रही हैं जिनका कई कारणों के चलते दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज संभव नहीं हो पाता। इस योजना के लिए भी अगले साल 50 करोड़ रूपये का बजट इसमें प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय ये तो सब इन्फ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ फैसिल्टीज को आगे बढ़ाने से सम्बन्धित काम है लेकिन इसके अलावा दो बड़े कदम जो सरकार उठाने जा रही है और जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और इस साल से उन पर काम शुरू हो जायेगा वो है उसमें पहला है हास्पिटल इन्फार्मेशन मैनेजमेन्ट सिस्टम और हेल्थ कार्ड। इसके तहत सारे नागरिकों को, दिल्ली के सब नागरिको को उनकी मतदाता पहचान या जनसंख्या रजिस्टर के आधार पर क्यू आर कोड बेस्ड ई–हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा इससे रोगियों की पहचान करने और जियो टैगिंग के साथ उनकी बीमारी की बुनियादी जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ये प्रणाली फेमिली ट्री यानी परिवार के सदस्यों की जानकारी उनकी बीमारी वगैरह का डिटेल लेने में मदद करेगी इससे दिल्ली के सभी नागरिकों को बेहतर और समय पर इलाज करवाने में आसानी हो जायेगी। इस योजना के लिए अगले साल के लिए मैं 160 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित कर रहा हूँ। दूसरा है हेल्थ हेल्पलाइन। जो हेल्थ कार्डधारक होंगे उनके लिए एक नि:शुल्क हेल्थ हेल्पलाइन

शुरू की जायेगी जो 24 घंटे हेल्पलाइन होगी। इसमें फोन करके कोई भी हेल्थ कार्ड का धारक किस बीमारी के लिए कहाँ इलाज कराना है, क्या करना चाहिए जैसी सलाह ले सकते हैं और इस हेल्पलाइन पर हेल्थ कार्डधारकों को हास्पिटल में अप्वाइन्टमेन्ट, डॉक्टर से अप्वाइन्टमेन्ट देने की भी फैसिल्टी दी जायेगी। तो ये दो बड़े इम्पार्टेन्ट चीजें आगे रिफार्म होंगी।

मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में आम जनमानस को स्वस्थ रखने के लिए योग और ध्यान को आम जनमानस तक निःशुल्क ले जाने के लिए आम आदमी योगशाला शुरू की गयी है। इसकी घोषणा मैंनें पिछले बजट में की थी और मुझे खुशी है कि कोरोना के लहरों के बीच भी दिल्ली सरकार के डिपसारू यूनिवर्सिटी में ट्रेन्ड 450 योग्य शिक्षक, योग शिक्षक रोजाना 15000 से अधिक लोगों को उनकी सुविधा और समय के अनुसार योग की योगशाला चला रहे हैं। लोगों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए अपने आप में ये एक बहुत बड़ा अभियान है जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि योग को हमें जनान्दोलन बनाना है। उसके संकल्प के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये योजना अगले साल भी चलती रहेगी। इसके लिए बजट में अलग से 15 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय जब मैं सदन के समक्ष केजरीवाल सरकार का मॉडल रोजगार बजट पहली बार लेकरके आया हूँ तो थोड़ी सी बात मैं स्वास्थ्य और रोजगार के रिश्ते पर भी करना चाहता हूँ। ये भी

इम्पार्टेन्ट है इस सदन को इन्फार्मेशन है। अगर कोविड की बीमारी नहीं होती तो शायद लोगों का ध्यान इस ओर नहीं जाता कि किसी देश की आर्थिक प्रगति का उस देश के लोगों के स्वास्थ्य से सीधा सम्बन्ध होता है। नीति विश्लेषक और आर्थिक इतिहास के विशेषज्ञ ने ज्ञानेन्द्र सेन गुप्ता ने लिखा है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था आर्थिक चर्चाओं का हिस्सा होती नहीं है। ये ट्रेजडी है हमारे देश में थोड़ी सी कि हमारी जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है जब हम आर्थिक चर्चा करते हैं तो अपनी हेल्थ फैसिल्टीज, हेल्थ डवलपमेन्ट, हेल्थ की बात नहीं करते। हम आर्थिक बात करते हैं, आर्थिक प्रगति की बात करते हैं। वो कहते हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था आर्थिक चर्चाओं का हिस्सा नहीं होती लेकिन महामारी के बाद दुनिया समृद्धि के जो नये पैमाने लागू करेगी उसमें ये तय होगा कि जिस मुल्क का स्वास्थ्य ढाँचा जितना चुस्त होगा उस पर उतने बड़े दाँव लगाये जायेंगे। ये आगे आने वाले समय के लिए बड़ी वर्ल्ड इकोनॉमीज के बारे में फोरकॉस्ट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे-जैसे हमारी आबादी की उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे उसकी प्रोडक्टीविटी कम होती रहती है। ऐसे में वर्किंग पापुलेशन से और ज्यादा बेटर प्रोडक्शन की जरूरत है। ऐसा करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना एकमात्रा रास्ता है और 55 साल की उम्र से उन्होंने एक एक्जाम्पल दिया कि 55 साल की उम्र वाले व्यक्ति से 45 साल की उम्र वाले का काम कराया जा सके, ये हेल्थ सिस्टम ही कर सकता है। उतनी प्रोडक्टीविटी। तो आगे की इकोनॉमी वर्ल्ड

इकोनॉमी इसी से निकलेगी कि किसका हेल्थ सेक्टर कितना मजबूत है। आज हमारे देश में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की और तकनीकों की कमी नहीं है। नये-नये प्रयोग और अविष्कार लगातार हो रहे हैं। लोगों को बीमारी से बचाकरके और खासतौर से उनको प्राथमिक उपचार सही से और समय पर उपलब्ध कराकरके अपनी बड़ी आबादी को हम, सेहत को बचा सकते हैं। मैकेन्जी की एक रिपोर्ट कहती है कि प्रति 100 डालर के खर्च से जीवन में एक वर्ष स्वास्थ्य का और बढ़ाया जा सकता है। अगर सरकार 100 डालर खर्च करती है तो एक व्यक्ति का एक साल उसका हेल्थ ईयर और बढ़ जाता है।अलग-अलग बीमारियों पर नियंत्रण, तुरन्त उपचार और सभी को स्वास्थ्य जैसी कोशिश किसी भी देश के लिए उसकी गारंटी है, उसकी ग्रोथ की गारंटी है। मैकेन्जी की गणना है कि स्वास्थ्य सेवायें बेहतर कर 2040 तक दुनिया के जीडीपी में 12 ट्रिलियन डालर जोड़े जा सकते हैं जो ग्लोबल जीडीपी का 8 परसेन्ट होगा यानी कि 0.4 परसेन्ट की हर साल की उसकी बढ़ोत्तरी। भारत में सरकारों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर निवेश करने में 100 रूपये के निवेश पर अर्थव्यवस्था में 400 रूपये का रिटर्न सम्भव है। स्वास्थ्य सेवायें बेहतर करने से जीवन में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष करीब 24 स्वस्थ दिन बढ़ाये जा सकते हैं। कुछ डेटा है जो बड़ा इम्पार्टेंट है। हेल्थ पैक्टसरकारों को क्यों करना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर के हवाले नहीं छोड़ देना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं पर बेहतर करने से जीवन में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष करीब 24 स्वस्थ

दिन बढ़ाये जा सकते हैं और 2040 तक जीडीपी में 45 हजार अरब डालर जोड़े जा सकते हैं जो भारत के कोविड के पहले की जीडीपी का 6 परसेन्ट होगा। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए पिछले 7 साल से दिल्ली सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगातार अपने खर्चे को बढ़ाती आ रही है और बात सिर्फ लोगों को स्वस्थ रखने की नहीं है बात लोगों को स्वस्थ रखते हुए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की है। इसीलिए मैंने बात की। और नए नए रोजगार के अवसर पैदा करने की है। 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 9769 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान मैं प्रस्तावित करता हूँ इसमें 7522 करोड़ रूपये का राजस्व बजट और 2247 करोड़ रूपये का पँजीगत बजट शामिल है, 5567 करोड़ रूपये की राशि स्वास्थ्य क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित की गयी है।

शिक्षा

अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी बात स्वास्थ्य के बाद शिक्षा के लिए करना चाहता हूँ। Kejriwal model of Governance के पिछले 7 साल के दौरान दिल्ली को मजबूत बनाने के लिए 5 महत्वपूर्ण पिल्लर रहे हैं बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आज दुनियाभर में हम जिन देशों को विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में देख रहे हैं उनमें अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का इतिहास 3 महत्वपूर्ण कारकों पर रहा है - अर्थव्यवस्था की परंपरागत ताकत, दूसरा सरकारों का राजनीतिक साहस और दूरदर्शिता और तीसरा

आबादी की शिक्षा की क्वालिटी। क्वालिटी एजुकेशन कैसे दी जा रही है। परंपरागत रूप से देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था एक मजबूत अर्थव्यवस्था रही। हमारी ताकत हमेशा हमारे लोग और हमारे प्राकष्टतिक संसाधन हमारे पास उपलब्ध रहे। इसके बावजूद अगर आजादी के 75 साल में हम एक डेवलप्ड इकॉनॉमी नहीं बन पाए और केवल developing economy बनकर रह गए तो इसका एक बड़ा कारण है अध्यक्ष महोदय कि सरकारों नें राजनीतिक साहस और दूरदर्शिता से काम नहीं लिया। 2015 में ऐसी गलती को ठीक करते हुए Kejriwal model of Governance के तहत हमारी सरकार ने साहसिक और दूरदर्शी कदम यह उठाया कि बड़ी बड़ी प्राथमिकताओं को किनारे करते हुए, जो पारंपरिक प्राथमिकताएं थी उनको किनारे करते हुए, बड़ी बड़ी इच्छाओं को किनारे करते हुए, शिक्षा को सबसे बड़ी राजनीतिक प्राथमिकता हमने बनाया और पिछले 7 साल में इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए, इस पर काम करते हुए लगातार शिक्षा के बजट में सबसे ज्यादा आवंटन किया और इस आवंटन के दम पर शानदार सरकारी स्कूल बिल्डिंग्स बनी, स्कूलों में शानदार लैब, लायब्रेरी, क्लासरूम बने, बैठने के लिए अच्छी डेस्क मिली बच्चों को, 21वीं सदी की आधुनिक डिजिटल पढ़ाई बच्चों को मिलनी शुरू हुई, टीचर्स की देश विदेश में ट्रेनिंग हुई, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिली। 2015 में अध्यक्ष महोदय, अगर ये कदम नहीं उठाए गए होते तो आज दिल्ली के ज्यादातर सरकारी स्कूल टेंट वाले स्कूल की पहचान बनाए रखते जो उनको पहले पहचाना

जाता था। 7 साल की इस यात्रा के बाद मैं बड़े आत्मविश्वास और भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति ने दिल्ली में अर्थव्यवस्था की क्रांति का आधार रखा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब तक कोरोना की महामारी के बावजूद सीबीएसई परीक्षा में सबसे बेटर रिजल्ट प्राप्त किए, लगभग असंभव समझे जाने वाले 100 परसेंट रिजल्ट एक्चुअली 99.84 परसेंट रिजल्ट बट एवरेज 100 परसेंट को हासिल करके दिखाया है। अब दिल्ली में अमीर हो या गरीब, सबके बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा लेकर नीट और आईआईटी जैसी परीक्षाएं पास कर रहे हैं, नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन के नए मापदंड तय करने के लिए हमने Delhi School Education Board का गठन किया है और साथ में दिल्ली में अलग अलग विषयों की specialize पढ़ाई के लिए School of Specialize Excellence खोले हैं। इन स्कूलों में पढ़ाई के लिए अन्तर्राष्ट्रीय तरीके अपनाए जा रहे हैं और बच्चों के सीखने की प्रक्रिया का आंकलन भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। ये स्कूल प्रमुख विश्वविद्यालयों, विशेषज्ञों, उद्योग जगत के साथ भी साझेदारी करते हैं ताकि इंटर्नशिप, इनकी apprenticeship, master classes, guest lecture, field visit के माध्यम से सीखने की इनकी प्रक्रिया को और डीप किया जा सके। दिल्ली के सारे स्कूलों में शुरू किया गया happiness और देशभक्ति कार्यक्रम भी entrepreneurship के बारे में मैं पहले बोल चुका हूँ लेकिन तीनों happiness पाठयक्रम, देशभक्ति

पाठयक्रम और entrepreneurship पाठयक्रम इतने attract कर रहे हैं लोगों को कि प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स अब उसकी डिमांड कर रहे हैं और अभिभावक और अधयापकों की मांग पर अब दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में भी happiness और देशभक्ति पाठयक्रम और entrepreneurship पाठयक्रम शुरू किए जा रहे हैं। महोदय मैं 2022-23 के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में लागू किए जाने वाले चंद नए कार्यक्रम भी प्रस्तावित कर रहा हूँ। चिराग एनक्लेव नई दिल्ली में एक स्कूल साईस म्यूजियम स्थापित करने का प्रस्ताव है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच विज्ञान के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो किताबों और वीडियोज़ के माध्यम से विज्ञान को तिलिस्म की दुनिया लगते हैं, इस संग्रहालय में जाकर, नए साईस म्यूजियम में जाकर बच्चे उनको आसानी से समझ सकेंगे। ये school science museum बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और रूचि विकसित करेगा और उनके fundamental clearance उनके thoughts को देगा। अध्यक्ष महोदय, बेघर परिवारों के बच्चे जो सड़क के किनारे, फुटपाथ, फ्लाईओवर, सीढ़ियों के नीचे, खुले हुए पूजा स्थलों पर, मंडप में, रेलवे प्लेटफार्म पर रहते हैं, आश्रय के लिए, भोजन के लिए, शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित रह जाते हैं। सरकार ने इन बच्चों को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराने के कई स्टेप्स लिए हैं लेकिन वो अभी पार्टली सक्सेसफुल हुए हैं और ये गुणवतापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि भोजन और आश्रय जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं हो

जाए क्योंकि बच्चों को हम स्कूल लाते हैं इन जगहों से बेआश्रय बच्चों को, वो भोजन के लिए या शेल्टर के लिए कहीं और चले जाते हैं। तो बड़ा सिस्टम गड्डमड्ड है। तो कम उम्र के इन सुविधावंचित बेघर बच्चों को भविष्य की चिंता करते हुए दिल्ली सरकार ने आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बोर्डिंग स्कूल homeless बच्चों के लिए एक Boarding school बनाने का फैसला लिया है। ये स्कूल बच्चों को शिक्षा के साथ साथ रहने की सुविधा भी देंगे और उनको समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास भी करेंगे, इसके लिए मैं 10 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूँ।

मैंने अपने पिछले बजट में सभी क्लासरूम्स को अगले 5 साल में डिजिटल क्लासरूम में बदलने की शुरूआत की योजना रखी थी। इसका पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो गया और अगले 4 साल में हम अपने सभी स्कूलों के क्लासरूम्स को डिजिटल क्लासरूम्स में बदलने का काम इस साल से शुरू कर रहे हैं। राजेन्द्र नगर के एक स्कूल में एक आधुनिक मोंटेसरी लैब बनाई है। early childhood education की दिशा में मोंटेसरी लैब बड़ी अहम भूमिका निभाती हैं। आने वाले समय में हम 100 स्कूल्स में ऐसी ही modern montessori lab बनाएंगे। 100 चयनित स्कूलों में स्थानीय बच्चों और समाज की जरूरतों के हिसाब से local needs के हिसाब से sports infrastructure पर काम हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, स्कूल की शिक्षा के बाद दिल्ली सरकार ने higher technical education संस्थानों के विस्तार पर भी पिछले 7 साल में बहुत काम किया है।

2015 में सरकार बनने के बाद केजरीवाल जी सरकार की तरु से दिल्ली में अब तक 5 नई universities बन चुकी हैं। 2015 में Pharmaceutical Science and Research University (DPSRU) बनी, इसके बाद 2018 में Netaji Subhash University of Technology (NSUT) बनी, 2020 में Delhi Skill and Entrepreneurship University (DSEU) बनी, 2021 में Delhi Sports University बनी और 2022 में Delhi Teachers University बनी। इसके अलावा Ambedkar University के दो नए कैंपस कर्मपुरा और लोधी रोड पर खोले गए। डीटीयू का ईस्ट दिल्ली कैंपस खोला गया और आईपीयू का ईस्ट दिल्ली कैंपस इस साल से शुरू हो रहा है। अगले साल अगर दिल्ली के स्कूलों से निकल रहे छात्रों के क्योंकि हमारे स्कूल से बच्चे higher education में जाते हैं तो वहां सीट्स की बहुत कमी थी तो कितना काम हुआ उसको भी मैंएक मिनट में रखना चाहता हूँ कि स्कूलों से निकल रहे छात्रों के higher education में बढ़ रहे अवसरों को देखें तो पिछले 7 साल में केजरीवाल सरकार के दौरान इसमें बहुत शानदार काम हुआ है। मैं थोड़ा सा डेटा आपके सामने रखता हूँ। Delhi Technical University, DTU 2014 में जब सरकार आई थी 2014 के दौरान तो वहां 2226 बच्चों को एडमिशन मिलता था, 2021 में 4105 हो गयी है इनटेक। 2226 से बढ़कर 4105 हो गया है। NSUT उस वक्त NSIT था 913 बच्चे उसमें दाखिल होते थे, अब 3200 बच्चे वहां दाखिल होते हैं हर साल। IP University 28000 सीटें थी वहां इनटेक की, अब 38000 इनटेक

हो गया है IP University का। IG DTUW 300 सीटें थी वहां पर इनटेक की, अब 1350 सीट हो गयी हैं वहां पर इनटेक की। नए बच्चे वहां हर साल दाखिला लेते हैं 1350 Ambedkar University 2014 में 1800 सीटें थी अब 4700 सीटें उसकी इनटेक हो गयी है। Delhi Skill नई यूनिवर्सिटी बनाई है Delhi Skill & Entrepreneurship University. इसके 15 कैंपस इस साल से शुरू हो चुके हैं इसमें Graduation, Post Graduation, B.Tech, Diploma आदि कोर्सिस के लिए 7145 नई सीटों पर इसमें एडमिशन हुए और इस साल 15 कैंपस शुरू हुए, अगले साल इसके 11 कैंपस और शुरू हो रहे हैं और उसमें भी करीब ढाई हजार नई सीटें इसमें और बन जायेंगी। तो higher education के avenues भी दिल्ली में खूब बढ़े हैं। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय, इसने अपना काम शुरू कर दिया है। जैसे मैंने पहले भी सदन में कहा था कि Delhi Sports University की संकल्पना एक ऐसी यूनिवर्सिटी के रूप में की गयी है जहां केवल देश को अच्छे खिलाड़ी, मेडल लाने वाले खिलाड़ी पर काम होगा। इसमें कोई स्पोर्ट्स से रिलेटिड जॉब और उसके मैनेजमेंट और इन सब पर नहीं, केवल और केवल खिलाड़ी तैयार करने पर होगा और मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि अगले सेशन से यानि अगले academic session से दिल्ली खेल विश्वविद्यालय में देशभर से करीब 250 खेल प्रतिभाओं को दाखिला देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है और इन खेल प्रतिभाओं को अभी से भावी ओलंपियन के रूप में तैयार किया

जाएगा। इसी तरह हाल में शुरू की गयी Delhi Teacher University ने भी बहुत तेजी से अपना काम करना शुरू कर दिया है और हमारी पूरी कोशिश है कि भारत सरकार से जरूरी मंजूरी लेने के बाद अगले सत्रा से यहां भी बी.एड. की पढ़ाई शुरू हो जाए। महोदय मैं वितवर्ष 2022-23 के लिए एजुकेशन सेक्टर में 16278 करोड़ रूपये के कुल खर्च का प्रस्ताव करता हूँ इसमें 14412 करोड़ रूपये राजस्व के तहत और 1866 करोड़ रूपये पँजीगत व्यय के तहत शामिल हैं।

आवास और शहरी विकास

थोड़ी सी बात आवास और शहरी विकास के संबंध में। हमारी सरकार ने अनधिकृत कालोनियों और दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में infrastructure development को हमेशा महत्व दिया है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सीसीटीवी कैमरा लगवाने, स्ट्रीट लाईट लगवाने, सड़क बनवाने, सीवर, पाक्र आदि का निर्माण कराने का काम प्राथमिकता पर पूरा कर लिया गया है। हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले यह काम बहुत छोटे पैमाने पर 895 कालोनियों तक सीमित थे, उन्हीं कालोनिज में कुछ कुछ होता था लेकिन 2015 में यह सुविधाएं प्रत्येक अनधिकृत कालोनी और झुग्गी बस्ती को तेजी से उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 1797 unauthorized colonies में से 1414 में निर्माण कार्य या तो पूरा हो चुका है या प्रगति पर है। मैं 2022-23 के लिए इस बजट में 1300 करोड़ रूपये का प्रस्ताव करता हूँ।

ड्यूसिब - दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ड्यूसिब के सराहनीय कार्यों से उत्तरी निगम, दक्षिणी निगम और पूर्वी निगम की सभी बस्तियों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। 634 बस्तियों में लगभग 1051 किलोमीटर की सीमेंटिड कंक्रीट फुटपाथ बनाई गयी है और 266 किलोमीटर लंबे नालों का निर्माण झुग्गियों में कर लिया गया है। महोदय, मैं वित्तवर्ष 2022-23 के बजट में आवास और शहरी विकास योजनाओं के लिए 5766 करोड़ रूपये का प्रावधान करता हूँ।

जल आपूर्ति और स्वच्छता

एक और महत्वपूर्ण सेक्टर जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिसके बारे में बात करते हैं सबसे close to his heart है वो है वाटर सेक्टर। जल आपूर्ति और स्वच्छता। दो और बड़े सपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों को देखने के लिए भरोसा दिया है और उस पर मुख्यमंत्री जी दिनरात काम कर रहे हैं वो हैं कि दिल्ली में 24 घंटे पीने के पानी साफ लोगों के घरों में आए और हमारी जो यमुना है वो निर्मल, साफ, सुंदर, निर्मल यमुना बन जाए। जैसा कि मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी दिन-रात इन दोनों सपनों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। जिस तरह 2015-16 में उन्होंने दिल्ली-वासियों के लिए 24 घंटे बिजली का सपना सच करके दिखाया वैस ही अब केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में 24 घंटे पीने के पानी मिलने का सपना भी जल्दी ही सच होगा। मुझे सदन को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली में पानी की

उपलब्धता 10 परसेंट बढ़ चुकी है। पहले दिल्ली में रोजना 915 एमजीडी पानी उपलब्ध होता था, अब यह 985 एमजीडी हो गया है। दिल्ली को बाहर से मिल रहे पानी का बेहतर प्रबंधन, बारिश के पानी की बेहतर हार्वेस्टिंग, इससे आने वाले 3 साल में 24 घंटे पानी सुनिश्चित कर लिया जाएगा।

दिल्ली-वासियों को 20 किलो लीटर प्रति माह, प्रति उपभोक्ता पीने का पानी मुफ्त उपलब्ध कराने की जो योजना 2015 में शुरू की थी सरकार बनने के तुरंत बाद, वो इस साल भी जारी रहेगी। औसतन 6.50 लाख उपभोक्ताओं के पानी के बिल इस योजना के तहत हर महीने जीरो आते हैं, 6.50 लाख।

पूरी दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी में हंड्रेड परसेंट सीवर पहुंचाने का काम इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।

यमुना को साफ करने की माननीय मुख्यमंत्री जी की मुहिम अब आगे बढ़ चली है। यमुना में गिरने वाले सभी नालों को इंटरसेप्ट करके या तो एसटीपी में ले जाकर उनके पानी को साफ किया जाएगा या फिर उनका इनसीटू ट्रीटमेंट करके उसको साफ पानी में बदलकर ही तभी यमुना में छोड़ा जाएगा। ये सारी योजनाएं तेजी से चल रही हैं और 2 साल में यमुना को पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार का यह संकल्प है कि दिल्ली-वासियों की तरफ से गंदे पानी की एक बूंद भी यमुना में न गिरे।

गंदे नालों और सीवर के ट्रीटमेंट किए गए पानी को इस्तेमाल करने की पॉलिसी पर भी अमल शुरू कर दिया गया है जिसके अंतर्गत यह पानी बड़े ग्रीन बेल्ट्स को, फॉरेस्ट को, फॉर्म हाउसिस को, हॉर्टिकल्चर को दिया जाएगा। इससे हजारों बोरवेल भी बंद होंगे और नीचे का वाटर लेवल भी ऊपर आयेगा।

नजफगढ़ ड्रेन, इसको पुनर्जीवित करने के लिए विस्तृत योजना पर धरातल पर काम शुरू हो चुका है। पूरे नजफगढ़ ड्रेन में फ्लोटिंग वेटलैंड और फ्लोटिंग एयरेटर लगाकर यहां पानी को साफ किया जा रहा है। नजफगढ़ ड्रेन की इनसीटू सफाईका काम और उसकी दोनों तरफ की सड़कों के सौंदर्यीकरण का काम भी इसके साथ-साथ शुरू होगा। नजफगढ़ ड्रेन जो पहले साहिबी नदी के नाम से जाना जाता था, अब सीवर के गंदे पानी के कारण ये नजफगढ़ ड्रेन कहलाने लगा है, तो इसको साफ करके और इसके दोनों तरु की सड़कों का सौंदर्यीकरण करके इसको पर्यटन स्थल के रूप में, आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करके हम वापस दिल्ली को दिल्ली की साहिबी नदी का तोह्फा देंगे। इसके लिए अलग से 705 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है।

पर्यावरण और वन

अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण का विषय पूरी दिल्ली के लिए गंभीर चिंता का विषय है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, Bio-diversity में

कमी, noise pollution, दिल्ली के पर्यावरण की गंभीर चुनौतियां हैं। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए हमारी सरकार ने 1 अक्टूबर, 2021 से 28 फरवरी, 2022 के दौरान 10 point winter air action plan कार्यान्वित किया। इसके तहत पराली जलाने पर नियंत्रण, एंटी डस्ट कैंपेन, कूड़ा-करकट जलाने की रोकथाम, आतिशबाजी पर पाबंदी, स्मॉग टावर बनाना, अधिक पॉल्यूशन फैलाने वाले स्थानों की पहचान, ग्रीन वॉर रूम को मजबूत करना, ई-कचरा पार्क की व्यवस्था और वाहन प्रदूषण नियंत्राण के उपाय इसमें शामिल हैं।

दिल्ली सरकार ने न केवल हरित क्षेत्र के संरक्षण में बल्कि लगातार इसके विस्तार में भी अच्छी भूमिका निभाई है और मुझे इस सम्मानित सदन को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 7 प्रमुख बड़े शहरों में दिल्ली के पास सबसे बड़ा वन क्षेत्र, लगभग 194. 24 वर्ग किलोमीटर का है। दिल्ली का फॉरेस्ट और ट्री कवर 2019 में कुल geographical area के 21.88 परसेंट से बढ़कर 2021 में 23.06 परसेंट हो गया है, ये भी बढ़ गया है। सरकार ने पिछले 2 साल में 11 शहरी वन विकसित किए हैं जो तेजी से बढ़ रहे शहरी कंक्रीट निर्माण में एक हरित स्थल का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

महोदय, दिल्ली में बड़ी संख्या में पालतु पशु हैं और उनके लिए स्वस्थ देखभाल की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैं बजट में हर तरह के पशुओं के लिए, उपचार

के लिए, दिल्ली के 'पहले सरकारी पशु चिकित्सालय महाविद्यालय' की स्थापना के लिए नई स्कीम का प्रस्ताव करता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में पर्यावरण और वन क्षेत्र के लिए 266 करोड़ रुपए का बजट मैं प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, ईमानदारी और दूरदर्शिता के हर क्षेत्र में नए आयाम केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से निकले हैं। 21 वीं सदी में अपने किसी काम के लिए अगर नागरिकों को सरकारी दफतर के चक्कर लगाने पड़े तो यह सरकारों के पिछड़ेपन की निशानी है, दूरदर्शिता की निशानी नहीं है, सरकारी दफतर में भ्रष्टाचार की निशानी है। केजरीवाल सरकार ने ईमानदार और दूरदर्शी सरकार होने का परिचय देते हुए विभिन्न सरकारी दफतरों की सेवाओं को अब तक डोर स्टेप डिलीवरी से जोड़ा है।दिल्ली में अभी तक 100 तरह की सरकारी सेवाओं के लिए 4 लाख 11 हजार बार इसकी सेवाएं ली जा चुकी हैं। सरकारी दफतरों से भ्रष्टाचार खत्म करने और आम आदमी को रिश्वतखोरी से बचाने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी की यह क्रांतिकारी योजना भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तैयार हुई और इसी सदन में मेरे द्वारा प्रस्तुत पिछले 7 बजट में से एक में यहां पर प्रस्तुत की गई थी। आने वाले साल में डोर स्टेप डिलीवरी की सेवा तीन सौ तरह की सरकारी कार्यों और सेवाओं में जोड़ी जाएगी।

ट्रांसपोर्ट सेक्टर

अध्यक्ष महोदय, दफतरों, मैंने डोर स्टेप डिलीवरी की बात की, दफतरों के चक्कर न लगाने की जरूरत पड़े, इसकी बात की। लेकिन दफतरों के चक्कर लगाने से मुक्ति का सबसे शानदार कदम दिल्ली सरकार ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में उठाया है। आजादी के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने जाकर ट्रांसपोर्ट विभाग की उस खिड़की को ताला लगा दिया जिसमें लोगों को लंबी लाईन लगाकर खड़ा होना पड़ता था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उस खिड़की में होने वाले काम को, उस दफतर को, पूरी तरह से उस काम को पूरी तरह से फेसलेस कर दिया। मौजूदा समय में परिवहन विभाग फेसलेस रूप से 47 सेवाओं का संचालन कर रहा है और इस कार्यक्रम से, 7 मार्च, 2022 को ये किया गया था और 7 मार्च, 2022 से 11 लाख से अधिक आवेदक इसका लाभ उठा चुके हैं, फेसलेस सेवाओं का।

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है, नई गाड़ियों की खरीद के बाद लोगों को आरसी लेने के लिए सरकारी दफतरों में भागना पड़ता था, लेकिन गाड़ी बेचने वाले वाहन विक्रेता को ही अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आरसी देने का अधिकार दे दिया है। तो इससे लोगों को सरकारी दफतरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।

इसी तरह का एक और प्रोग्रेसिव कदम लर्निंग लाइसेंस बनाने की दिशा में भी उठाया गया है। लर्निंग लाइसेंस के लिए भी लोगों को लाईन में लगकर, धक्के खाकर लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ता था। अब दिल्ली में लर्निंग लाइसेंस बनाने के इच्छुक लोगों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नहीं आना पड़ता, चेहरा पहचानने वाले, artificial intelligence वाले सॉफ्टवेयर की मदद से आम लोग अपना लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस अब घर पर बैठकर बनवा ले रहे हैं। ये भी देश में पहली बार हुआ है। इसीलिए मैंने कहा transparency, honesty, दूरदर्शिता, विजन।

ट्रांसपोर्ट विभाग की एक और उपलब्धि से मैं इस सदन को अवगत कराना जरूरी समझता हूँ कि दिल्ली में पहली बार बसों का बेड़ा 7,003 क्रास कर चुका है। अब तक के दिल्ली के इतिहास में यह सबसे बड़ी बसों की संख्या है। 7,003 बसे, अध्यक्ष महोदय, कोई सरकार नहीं खड़ी कर पाई जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में, दिल्ली के बेड़े में 7,003 बसे जोड़ दी हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार 2019 से डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध करा रही है और मैं इस सुविधा को जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ और इसके लिए बजट में 250 करोड़ रुपए का आबंटन करता हूँ।

परिवहन और सड़क और पुलों के लिए कुल 9,539 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बजट में है।

रोड इंफ्रास्ट्रक्चर

महोदय, सरकार शहर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। आश्रम चौक पर अंडरपास का काम पूरा हो चुका है। प्रगति मैदान पर दूसरा अंडरपास मई 2022 तक तैयार हो जाएगा। दिल्ली में 5 पुल, 2 अंडरपास और 1 पैदल सब-वे और डीएनडी फ्लाईओवर का आश्रम तक विस्तार का कार्य 2022-23 में पूरा हो जाएगा। इससे त्रिनगर, इंद्रलोक, कर्मपुरा, रामपुरा, नांगलोई, बसई दारापुर, कोंडली, आश्रम चौक से भीड़-भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। मैं इन परियोजनाओं के लिए 2022-23 में 114 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

डीएमआरसी करावल नगर, घोंडा और मंगल पांडे मार्ग के बृजपुरी जंक्शन पर एलिवेटेड कॉरिडोर सहित फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कर रही है। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

सरकार दिल्ली के नागरिकों के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में करीब 11,000 निःशुल्क वाईफाई हॉट-स्पॉट स्थापित कर चुकी है। औसतन 4 लाख लोग प्रतिदिन इन सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं।

महोदय, हमारी सरकार ने आजादी के 75 वें वर्ष के समारोहों के अंतर्गत दिल्ली में 500 स्थानों पर भव्य राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बनाई थी। सम्मानित सदन को यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि अब तक दिल्ली के विभिन्न स्थलों पर 175 राष्ट्रीय

ध्वज लहराए जा चुके हैं और शेष काम अगस्त 2022 तक, आजादी के 75 वें वर्ष में ही पूरा कर लिया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा और वेल्फेयर

अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी बात सामाजिक सुरक्षा और वेल्फेयर के काम पर भी मैं रखना चाहूँगा। जब कोविड के दौरान लोगों की नौकरियां गई और लोगों के व्यापार बंद हुए, लोगों ने जब अपनी जान गवाई, परिवारों में कमाने वाला व्यक्ति कोविड का शिकार होकर उनको छोड़कर चला गया तो उस दौरान केजरीवाल सरकार एक परिवार की तरह से उन परिवारों के साथ खड़ी हुई। एक बड़े भाई की तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने एक-एक परिवार के दर्द को समझा। दिल्ली पहला ऐसा राज्य था जहां ये योजना बनाई गई कि कोविड के कारण जिस व्यक्ति की भी मृत्यु हुई है उसके परिवार को तुरंत 50 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अब तक 27,322 परिवारों को इस योजना के तहत राशि दी जा चुकी है।

सिर्फ इतना ही नहीं कोविड के कारण अगर किसी परिवार ने अपना कमाऊ सदस्य का साथ खो दिया है तो दिल्ली सरकार की ओर से उसके आश्रितों को ढाई हजार रुपये प्रतिमाह की पेंशन शुरू की गई है। यहां ये भी गौरतलब है कि ये पेंशन उस परिवार को मिल रही किसी अन्य पेंशन, अगर उसको कोई और पेंशन मिल रही है तो उसके ऊपर दी जाएगी, उससे अलग दी जाएगी। कोविड

के कारण अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई और इलाज का खर्चा सरकार उठा रही है और साथ ही प्रत्येक बच्चे की ढाई हजार रुपये प्रति महीना पेंशन भी दे रही है।

महोदय, हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और सुविधा वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को लेकर काफी सक्रिय है। इसके तहत 8.50 लाख लाभार्थियों के लिए 2,000 से 2,500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जा रही है। मैं वर्ष 2022-23 में इन लाभार्थियों के लिए 3,063 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव करता हूँ। एससी/एसटी और गरीब परिवारों से आने वाले छात्रों के डाक्टर, इंजीनियर या वकील या सिविल सर्विस में जाने के सपने के लिए इसके लिए दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है। इसके तहत करीब 13,136 युवा दिल्ली के सुप्रसिद्ध कोचिंग संस्थानों से अपने कैरियर की परीक्षा की कोचिंग ले रहे हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए मैं इस योजना के तहत 160 करोड़ रुपये की परिव्यय का प्रस्ताव कर रहा हूँ।

बजट अनुमान 2022-23 के लिए समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के लिए 4,843 करोड़ रुपये की राशि का मैं प्रावधान करता हूँ।

श्रम

अध्यक्ष महोदय, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में दिल्ली का श्रमिक दिल्ली की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा रहा है और जैसा मैंने अभी जिक्र किया है कि दुनिया में इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए मजदूरों के भी वेतन को बहुत कंसीडर किया गया, हमेशा कंसीडर किया गया। इसलिए 2015 में ही इसका आधार रखा गया दिल्ली में और दिल्ली सरकार ने 2015 में ही दिल्ली में ही श्रमिकों का न्यूनतम वेतन देश में सबसे ज्यादा कर दिया और आज भी मिनिमम वेजिज दिल्ली में सबसे ज्यादा है।

कोविड की महामारी के दौरान काम और बाजार बंद होने का सबसे ज्यादा असर श्रमिकों के ऊपर पड़ा है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित निर्माण श्रमिक हुए हैं, निर्माण श्रमिकों के दर्द को समझते हुए दिल्ली सरकार ने बड़े पैमाने पर निर्माण श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन की मुहिम चलाई और श्रमिकों को सहायता देने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए 500 करोड़ रुपये की राशि 5 लाख से ज्यादा निर्माण श्रमिकों के खाते में सहायता के रूप में दी।

पावर

पावर सैक्टर अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के नागरिकों को अब चौबीस घंटे सातों दिन आप बिना किसी परेशानी के बिजली आपूर्ति की जा रही है। 200 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए सरकार की शून्य बिजली बिल योजना बेहद

स्फल रही है और ऊर्जा संरक्षण में इसका बहुत योगदान रहा है। सरकार 1984 के दंगा पीड़ितों को 400 यूनिट तक बिजली की खपत के लिए 100 परसेंट सब्सिडी भी देती है। विद्युत सब्सिडी योजना का विस्तार न्यायालय परिसर के भीतर वकीलों के कक्षों तक भी कर दिया गया है। इसी तरह दिल्ली के सभी कृषि उपभोक्ताओं को भी कनेक्शन के लिए सब्सिडी दी जाती है। ये योजनाएं केजरीवाल मॉडल ऑफ़ गवर्नेंस की स्तंभ पहचान है।मैं 2022-23 के बजट में बिजली सब्सिडी के लिए 3250 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

भाग-ख

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने बजट वक्तव्य का भाग-ख प्रस्तुत करता हूँ जो राजस्व से संबंधित है। बजट भाषण के पहले भाग तें मैंने विस्तार से सरकार की रोजगार और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की नीतियों की चर्चा की है, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार लगातार अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। कोविड के कारण पिछले साल हमारे रेवेन्यू में काफ़ी कमी रही। हालांकि 2021-22 के लिए रेवेन्यू कलेक्शन में पिछले साल की तुलना में संतोषजनक बढ़ोतरी भी हुई। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान फरवरी 2022 तक हमने 35,112 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कलेक्शन किया है, इसमें पिछले वर्ष (फरवरी 2021) की तुलना में 39 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। ईमानदार प्रशासन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी

के माध्यम से सतर्कता के चलते सरकार कर चोरी को रोकने में काफी हद तक सफल रही है।

जीएसटी और वैट, सरकार के लिए रेवेन्यू के सबसे बड़े सोर्सिज हैं। 2021-22 में (फरवरी 2022 तक) जीएसटी और वैट के लिए टैक्स कलेक्शन 24,380 करोड़ रुपये रहा, जिसमें पिछले साल की तुलना में 42 परसेंट करीब वृद्धि हुई है।

महोदय, हमारी सरकार ने रेवेन्यू बढ़ाने और टैक्सपेयर की सुविधा के लिए अनेक उपाय किए हैं। हमने हरेक टैक्स वार्ड की 14 प्रमुख के.पी.आई. पाइंट्स के साथ मॉनिटरिंग मंथली परफार्मेंस मॉनिटरिंग शुरू की है, हरेक टैक्स वार्ड की मॉनिटरिंग शुरू की है। दिल्ली में कर विभागों में इंस्पेक्टर राज पूरी तरह से बंद किया गया है और सर्वे और स्क्रूटनी के लिए केवल जीएआईएन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं और उसका जो इंटेलीजेंस और एनालिटिक्स है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। टेक्नीकल एनालिसिस से मिले सुरागों के आधार पर अप्रैल, 2021 से फरवरी, 2022 तक 156 सर्वेक्षण किए गए इसके अलावा कोई स्क्रूटनी नहीं हुई। इसके अलावा कहीं कोई सर्वे नहीं हुआ कहीं रेड नहीं डाली गई और सरकार को देय 38.76 करोड़ रुपये का पता लगाया, जिसमें से 26.57 करोड़ रुपये की रिकवरी हो चुकी है। उन करदाताओं के लिए ई-इन्वॉयस भी अनिवार्य कर दिया गया जिनका टर्नओवर 1 अप्रैल 2021 से शुरू वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपये से अधिक था।

महोदय, देश में पेट्रोल और डीजल की दरों में ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों द्वारा ईंधन का मूल्य बढ़ाने के कारण बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमतों में लगातार वृद्धि आम लोगों के लिए चिंता का विषय रहती है। हमारी सरकार ने नागरिकों को राहत देने के लिए पेट्रोल की बिक्री पर वैट रुपये में 30 पैसे से कम करके 19.40 रुपये कर दिया था। इस की हम घोषण कर चुके हैं। सरकार ने लोक हित के मुद्दे को जीएसटी परिषद की बैठकों में सक्रियता से उठाया है उसमें कुछ फैसले दिल्ली के संबंध में लिए गए, दिल्ली के लोगों की, व्यापारियों की मांग पर लिए गए। कोविड-19 को उपचार में आने वाली 6 औषधियों को जीएसटी से मुक्त कराया गया। कैंसर के दवा पर जीएसटी 12 परसेंट से घटाकर 5 परसेंट कराया गया।

महोदय, हम दिल्ली के व्यापारियों को टैक्स संबंधित अनावश्यक मुकदमों से उलझाने से बचाने के लिए, मुकदमों की संख्या कम करने और लंबित मांगों की वसूली के लिए, जिसमें बकाया कर, ब्याज और जुर्माने की रकम शामिल है, कर माफी योजना का प्रस्ताव कर रहे हैं एमनेस्टी स्कीम आएगी इसके लिए। सरकार ने न्यू एक्साइज पालिसी के जरिये उपभोक्ताओं के अनुभव में व्यापक बदलाव लाने का प्रयास किया है। पुरानी प्रणाली को आबकारी राजस्व संग्रह की नई प्रणाली से पूरी तरह बदल दिया गया है। इससे प्रतिवर्ष सरकार को 4500 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

नई आबकारी नीति का उद्देश्य सरकार के लिए अधिकतम राजस्व सृजन पक्का करना और दिल्ली में गैर कानूनी और गैर शुल्क वाली शराब का उन्मूलन करना है ताकि समग्र व्यापार में कारोबार को आसानी सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक जटिल और अत्यधिक विनियमित आबकारी व्यवस्था को सरल बनाया जा सके।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी अवधि के दौरान राजस्व संग्रह को गति देने के लिए मौजूदा सर्किल दरों में 20 प्रतिशत की छूट की पेशकश की थी, जिसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में संपतियों का पंजीकरण हुआ और राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी भी हुई।

2021-22 के दौरान 16 मार्च, 2022 तक कुल रजिस्टर्ड डाक्युमेंट्स की संख्या 2,67,690 हो गई है और कुल रेवेन्यू कलेक्शन 4,680 करोड़ रुपये का हुआ। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रेवेन्यू कलेक्शन में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में करीब 28 परसेंट की वृद्धि हुई है।

सर्किल दरों में पुनरीक्षण के लिए माननीय उपराज्यपाल द्वारा गठित समिति के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सर्किल दरों के संशोधन के व्यापक प्रक्रिया जारी है।

अध्यक्ष महोदय, अब अंत में मैं कहना चाहूँगा कि मैंने आज अगले वित्त वर्ष के लिए जो योजनाएं और बजट प्रस्ताव इस सदन के समक्ष रखे हैं, उसमें दिल्ली के गवर्नमेंट सैक्टर, प्राइवेट सैक्टर,

दिल्ली के लोकल मार्किट, दिल्ली के शॉपिंग मार्किट, दिल्ली के ट्रेडर्स सबके लिए अपार संभावनाएं हैं। सरकार अपने प्रयासों से और प्राइवेट सैक्टर के साथ अच्छी नीयत की पार्टनरशिप करके दिल्ली की तरक्की को सुनिश्चित करेगी और दिल्लीवासियों के लिए सरकार और प्राइवेट सैक्टर की सहभागिता से रोजगार प्रदान करने के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। जिस तरह पिछले 7 साल में दिल्ली में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली आदि के काम का दिल्ली वालों को फायदा मिला है और पूरे देश की राज्य सरकारों ने, यहां तक की विपक्ष की राज्य सरकारों ने भी दिल्ली से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश की है, वो चाहे मौहल्ला क्लीनिक हो, मुफ्त बिजली पानी की स्कीम हो, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हो, हैप्पीनेस जैसे पाठ्यक्रम हो, डोर स्टेप डिलीवरी की योजना हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने की और बाकी राज्य सरकारों ने उनसे कुछ सीखा या उनसे कुछ सीखने का प्रयास किया।

मुझे पूरा यकीन है अध्यक्ष महोदय कि आज सदन में प्रस्तुत रोजगार बजट का सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली के लोगों को मिलेगा जहां के लोगों के लिए युवाओं के लिए नए-नए रोजगार के अवसर मिलेंगे और मुझे यह भी पूरा यकीन है कि आने वाले 1 या 2 साल के अंदर-अंदर सारी राज्य सरकारें दिल्ली के इस मॉडल को भी समझने की कोशिश करेंगी कि सरकार और प्राइवेट सैक्टर मिलकर जब एक साथ मिलकर राज्य की ग्रोथ के लिए काम करते

हैं तो नौकरियों और रोजगार के अवसर कैसे पैदा होते हैं, ये भी 1 से 2 साल के अंदर-अंदर बाकी राज्य सरकारें भी सीखने आ रही होंगी आप देखिएगा। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से देश ने सीखा है कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक हो सकते हैं, 24 घंटे मुफ्त बिजली कैसे दी जा सकती है, आने वाले समय में पूरा देश केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से यह भी सीखेगा कि ठीक से योजनाएं बनाकर एक बड़ी आबादी को रोजगार कैसे दिया जा सकता है। अन्त में आज के रोजगार बजट के परिणेता मार्गदर्शक और देश के करोड़ो युवाओं की उम्मीद दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी की तरु से दिल्ली और देश के युवाओं को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की चार पंक्तियों से मैं अपना बजट वक्तव्य संपन्न करूंगा। मुख्यमंत्री जी की तरफ से देश के युवाओं के लिए-

''दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य-प्रकाश तुम्हारा,

लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहार तुम्हारा।''

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अन्य सदस्यगण आपको बजट पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा न, बजट पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। बजट पर चर्चा होगी न, चर्चा में बात रखिऐगा ये। बजट में चर्चा होगी न, जो कुछ आपने कहना है बजट की चर्चा में कहिए। बैठ जाइए प्लीज बैठिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ बैठिए, बाजपेयी जी

बैठिए आप बैठिए। बाजपेयी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बैठिए, आप बैठिए प्लीज। आप बैठ जाइए बाजपेयी जी बैठिए प्लीज। बाजपेयी जी मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बैठिए, आप बैठ जाइए। आपको बजट पर बजट भाषण पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा तब चर्चा करिएगा, तब बात रखिएगा अपनी। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, बैठ जाइए प्लीज। बाजपेयी जी मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आपको बजट पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा उसमें चर्चा करिएगा। आप बैठ जाइए।

माननीय उप मुख्यमंत्रीः मैं अंत में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की चार पंक्तियां माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से देश के युवाओं को समर्पित कर रहा हूँ-

''दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य-प्रकाश तुम्हारा,
लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा।
जिस मिट्‌टी ने लहू पिया, वह फूल खिलाएगी ही,
अम्बर पर घन बन छाएगा उच्छवास तुम्हारा।
वह प्रदीप जो दिखा रहा है झिलमिल दूर नहीं है,
थक कर बैठ न जाना भाई मंजिल दूर नहीं है।''

बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जय हिन्द- जय भारत।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिये हो गया वाजपेयी जी, वाजपेयी जी बैठ जाईये आपको मैं बहुत देर से वार्निगं दे रहा हूँ बैठ जाईये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठिये-बैठिये, अब।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अब माननीय उप-मुख्यमंत्री वित्त वर्ष 2022-23 के लिए Demands for Grants पेश करेंगे।

माननीय उप-मुख्यमंत्रीः Hon'ble Speaker Sir, I present Demands for Grants for the Financial Year 2022-23 before the House.

माननीय अध्यक्षः इन अनुदान मांगों पर सदन में 29 मार्च, 2022 को विचार किया जायेगा। अनुदानों की पूरक मांगे 2021-2022 अब माननीय उप-मुख्यमंत्री वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सप्लीमेंटरी डिमांड पेश करेंगे।

माननीय उप-मुख्यमंत्रीः Hon'ble Speaker Sir, I present Second & Final Batch of Supplementary Demands for Grants for the financial year 2021-2022 before the House.

माननीय अध्यक्षः अब सदन Supplementary Demands पर Demands wise विचार करेगा। Demand No.2, General Administration जिसमें Revenue में 03 लाख रुपये हैं सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No.2 पास हुई।

Demand No.3, Administration of Justice जिसमें Revenue में 02 लाख 50 हजार रुपये हैं सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No.3 पास हुई।

Demand No.4, Finance जिसमें Revenue में 04 लाख 50 हजार रुपये हैं सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

SupplementaryDemand No.4 पास हुई।

Demand No.5, Home जिसमें Revenue में 02 लाख रुपये हैं सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

SupplementaryDemand No.5 पास हुई।

Demand No.6, Education जिसमें Revenue में 10 लाख रुपये हैं तथा Capital में 85 करोड़ रुपये हैं। कुल राशि 85 करोड़ 10 लाख रुपये सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

SupplementaryDemand No.6 पास हुई।

Demand No.7, Medical and Public Health जिसमें Revenue में 06 लाख रुपये तथा Capital में 01 लाख रुपये हैं। कुल राशि 07 लाख रुपये सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

SupplementaryDemand No.7 पास हुई।

Demand No.8, Social Welfare जिसमें Revenue में 15 लाख 50 हजार रुपये हैं सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

SupplementaryDemand No.8 पास हुई।

Demand No.9, Industries जिसमें Revenue में 02 लाख रुपये सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

SupplementaryDemand No.9 पास हुई।

Demand No.10 of Development जिसमें Revenue में 03 अरब 82 करोड़ 23 लाख 40 हजार रुपये तथा कैपिटल में 03 लाख रुपये कुल राशि 03 अरब 82 करोड़ 26 लाख 40 हजार रुपये है सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No.10 पास हुई।

Demand No.11, Urban Development and Public Works जिसमें Revenue में 16 लाख रुपये तथा कैपिटल में 14 लाख रुपये कुल 30 लाख रुपये हैं सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

SupplementaryDemand No.11 पास हुई।

हाउस ने कुल मिलाकर Revenue में 03 अरब 82 करोड़ 84 लाख 90 हजार रुपये तथा कैपिटल में 85 करोड़ 18 लाख रुपये कुल राशि 04 अरब 68 करोड़ 02 लाख 90 हजार रुपये की Supplementary Demand को मंजूरी दे दी है। The Delhi Appropriation (No.2) Bill, 2022' (Bill No.4 of 2022) अब माननीय उप-मुख्यमंत्री Delhi Appropiration (No.2) of Bill 2022, (Bill No.4 of 2022) को हाउस में Introduce करने की permission मांगेंगे।

माननीय उप-मुख्यमंत्रीः Hon'ble Speaker Sir, I seek permission of the House to introduce the Delhi Appropriation (No.2) Bill 2022, (Bill No.4 of 2022) to the House.

माननीय अध्यक्षः उप-मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

माननीय अध्यक्षः अब माननीय उप-मुख्यमंत्री बिल को सदन में introduce करेंगे।

माननीय उप-मुख्यमंत्रीः Hon'ble Speaker Sir, I introduce the Delhi Appropriation (No.2) Bill, 2022' (Bill No.4 of 2022) to the House.

माननीय अध्यक्षः अब बिल पर Clause wise विचार करेंगे। प्रश्न है कि खंड-2, खंड-3 व Schedule बिल का अंग बने

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

खंड-2, खंड-3 एवं Schedule बिल का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खंड–1 Preamble और Title बिल काअंग बने

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

खंड–1 Preamble और Title बिल काअंग बन गये।

अब माननीय उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि The Delhi Appropriation (No.2) Bill, 2022, (Bill No.4 of 2022)' को पास किया जाये।

माननीय उप–मुख्यमंत्रीः Hon;ble Speaker Sir the House may now please pass the 'The Delhi Appropriation (No.2) Bill, 2022 (Bill No.4 of 2022)'.

माननीय अध्यक्षः अब मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

The Delhi Appropriation (No.2) Bill, 2022 (Bill No.4 of 2022)' पास हुआ।

अब सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 28 मार्च, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है सभी माननीय सदस्य लंच के लिए सादर आमंत्रित हैं।

(सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 28 मार्च, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

... समाप्त ...

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।